www.tamsasanket.com
वर्ष: 29 || अंक 124 || अम्बेडकरनगर
शनिवार
25 जुलाई 2026 || पृष्ठ: 08 || मूल्य: ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

अम्बेडकर नगर व लखनऊ से एक साथ प्रकाशित

डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदय: 05:27
सूर्यास्त: 06:59
अधिकतम: 33°00
न्यूनतम: 28°00

पेज 07

विशेष समाचार | जल संकट का असंतुलित ... >>पेज 04 | योगी के पास एक लाख... >>पेज 06 | छात्रों की बात सुनना ..

पेपर लीक केस- कानूनी और क्रिमिनल एक्शन भी होगा, एक दिन पहले शिक्षा सचिव को हटाया था

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अफसर बर्खास्त

10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना

टाइमलाइन

संसद तक कैसे पहुंचा नीट विवाद

3 मई : देशभर में नीट-यूजी 2026 परीक्षा हुई। करीब 20 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए।

12 मई: पेपर लीक के आरोपों के कारण परीक्षा रद्द कर रि-एग्जाम की घोषणा की गई।

15 मई: सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं।

16 मई: अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू किया।

6 जून: कॉकरोच पार्टी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहला प्रदर्शन किया।

20 जून: कॉकरोच पार्टी ने जंतर-मंतर पर दूसरा विरोध प्रदर्शन किया गया।

28 जून: कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए।

20 जुलाई: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सीजेपी ने 'चलो संसद' मार्च निकाला। हजारों लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और टियर गैस का इस्तेमाल किया।

21 जुलाई: राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया, इन्हें हिरासत में लिया गया।

21 जुलाई: संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने नीट, लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा उठाया, दोनों सदनों में हंगामा हुआ।

22 जुलाई: विपक्ष ने संसद में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी रखा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई।

23 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा।

पेपर लीक पर क्या है कानून?

देश में पहले ही से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 लागू है। इसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू है। सरकार नए संशोधन कर कानून को और सख्त और प्रभावशाली करने की तैयारी में है।

इसके अलावा 1995 बैच के आईएएस अधिकारी टी.के. अनिल कुमार को पदोन्नत कर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

फैसला

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्रालय ने NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी। बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को 17 सीनियर अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन के आदेश जारी किए थे। सबसे बड़ा फेरबदल शिक्षा मंत्रालय में हुआ था। यहां 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। वे मौजूदा सचिव विनीत जोशी की जगह लेंगे।

>> (शेष पेज 06 पर)

फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया

उन्होंने यह भी कहा- हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है।दरअसल, यह पूरा मामला 3 मई को हुए NEET UG पेपर लीक से जुड़ा है। इसी NEET UG पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन अनशन किया और संसद में सांसद हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच CBI कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ताल हुई। अबतक 13 आरोपी पकड़े गए हैं। CBI जल्द ही इस चार्जशीट फाइल कर सकती है।

पेपर लीक संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक के प्रदर्शन के बीच कैबिनेट बैठक ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई। सरकार अगले सप्ताह में मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है। इस बिल में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। बिल में पेपर लीक के मामलों में 10 की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा। पेपर लीक विवाद और प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था। पीएम मोदी ने 2.56 मिनट का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया।

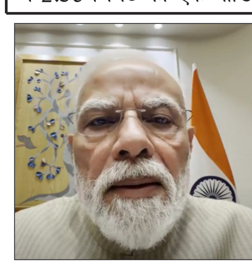

पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात अपने एक्स हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट किया

पीएम ने क्या कहा

वीडियो में पीएम ने कहा, ₹पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए यह पीड़ादायक है. इसलिए इस घटना के बाद सरकार ने कई क़दम उठाए हैं. गुनाहगारों को पकड़ा है और आज वे जेल में हैं. पीएम ने यह भी कहा कि पेपर लीक के बाद विद्यार्थियों का साल ख़राब न हो, इसका भी उनकी सरकार ने ख़्याल रखा।

मीडिया के सवाल पर बोले- नेक्स्ट पीएम मोदी ने कल कहा था- सख्त कानून लाएंगे

पेपरलीक संशोधन बिल पर मंत्री वैष्णव ने जवाब नहीं दिया

नई दिल्ली। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि यह बिल अब सोमवार 27 जुलाई को ही संसद में पेश किया जाएगा।

जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने आए तब उन्होंने पेपर लीक संशोधन बिल पर कोई जवाब नहीं दिया।

वैष्णव ने मीडिया के सवालों पर हर बार केवल एक शब्द कहा- नेक्स्ट।

>> (शेष पेज 06 पर)

धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री, इस्तीफा दें : राहुल

पैलेट गन से घायल छात्र की टी-शर्ट उठाकर घाव दिखाए

प्रेस कॉन्फ्रेंस

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। वे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं।' उन्होंने छात्र के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा, 'मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था, जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन कर रहा था।' 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च निकाला था।

>> (शेष पेज 06 पर)

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 27वें दिन खत्म

वांगचुक बोले- तीन मांगों पर लिखित आश्वासन मिला

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। NEET पेपर लीक के खिलाफ 27 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। वांगचुक ने शुक्रवार सुबह जारी वीडियो संदेश में कहा कि पिछले दो दिन से सरकार के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही थी। इस दौरान उनकी तीन प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से इन मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। वांगचुक ने कहा,सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज नहीं करने, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजन को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया।

मोदी बोले- वांगचुक डॉक्टरों का रुटीन फॉलो करें

>> (शेष पेज 06 पर)

फास्ट न्यूज

सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता पहुंचे भीमसेना प्रमुख को रोका

गुरुग्राम। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती सोनम वांगचुक हाल-चाल जानने पहुंचे भीमसेना प्रमुख एवं संविधान सुरक्षा पार्टी (एसएसपी) सुप्रीमो नवाब सतपाल तंवर को अस्पताल के मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया।

अलर्ट सतर्क

गुजरात में बाढ़ में कार बही, एक मंजिल तक पानी

अहमदाबाद/गुवाहाटी। देश के तीन राज्यों में भारी बारिश जारी है। गुजरात में कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। घर एक मंजिल तक डूब गए। अहमदाबाद, सूरत में पानी भर गया। असम में बाजार-पेट्रोल पंप डूब गए। यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सीतापुर में पानी सड़क पर भर गया। ग्रामीण नाव से आ-जा रहे हैं।

12वीं के स्टूडेंट का पोस्टर-तुम डंडे मारोगे, हम फूल देंगे

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन छात्र अपने-अपने अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से पहुंची पूजा ने अपने पोस्टर पर लिखा कि पुलिस की ड्रेस महज ड्रेस नहीं, एक वादा है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी और अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। वहीं, दिल्ली का 12वीं का स्टूडेंट ईशु एक पोस्टर लेकर पहुंचा।

अब सोशल-मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे

कोर्ट की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

निर्णय

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व अनुमति कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि इस आदेश का न्यूज रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और वीडियो शेयरिंग पर रोक लगाने की मांग वाली एक PIL पर अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने पत्रकार हर्षिता ग्रोवर की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते यह अंतरिम आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल या संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की पूर्व अनुमति के बिना न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को निकालना, संशोधित करना, प्रसारित करना, उससे कमाई करना, पोस्ट, रीपोस्ट या अपलोड करना प्रतिबंधित रहेगा। >> (शेष पेज 06 पर)

लाइव-स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग हो रहा है: याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता हर्षिता ग्रोवर की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि अदालतों की लाइव-स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मकसद न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। लेकिन, आम लोगों की कोर्ट की कार्यवाही तक पहुंच बढ़ाने के लिए किए गए इस उपाय का दुरुपयोग हो रहा है। लंबी सुनवाई से कुछ सेकंड या मिनट के अंश निकाले जा रहे हैं। उस दौरान कही जा रही बात को बिना सही संदर्भ समझे वायरल किया जा रहा है।

प्रधान के इस्तीफे पर सरकार आज जवाब देगी : सीजेपी

इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं प्रदर्शनकारियों के केस वापस लेने पर सहमति

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और CJP प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए।

बैठक के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष ने दैनिक भास्कर से कहा, 'हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है।'

>> (शेष पेज 06 पर)

डीएमआरसी ने दिल्ली में अगले आदेश तक नई दिल्ली समेत 18 मेट्रो स्टेशन बंद करने का आदेश दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक की जांच के लिए नागपुर और औरंगाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया है।

शिक्षा मंत्रालय में बड़े बदलाव, एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त

नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी।

बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को 17 सीनियर अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन के आदेश जारी किए थे।

जांच : सोशल मीडिया, सीसीटीवी फुटेज की जांच में पहचान हुई, पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में 216 क्रिमिनल शामिल : पुलिस

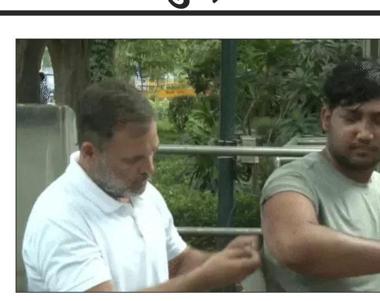

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (FCR) के जरिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों की पहचान कर रही है। 216 लोग ऐसे मिले हैं जिनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है।

इनमें वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और बाकी अन्य जिलों के हैं। सूत्रों के मुताबिक, वायरल सोशल मीडिया पोस्ट, सीसीटीवी फुटेज की FCR से जांच करने पर इन क्रिमिनल्स की पहचान हुई। जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई थी। कई वीडियोज ऐसे भी आए थे, जिनमें फोर्सेस पर भी हमला हुआ। फोर्सेस पर गलत बल प्रयोग के आरोप भी लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस प्रदर्शन की फुटेज और फोटो जांच रहा है।

पुलिस के किसी अधिकारी पर एक्शन नहीं

दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवेश कुमार श्रीवास्तव ने दैनिक भास्कर से कहा कि CJP प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी को सस्पेंड करने या विभागीय कार्रवाई करने की सोशल मीडिया पर आई खबर गलत है। पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कानून के तहत कार्रवाई की गई। जितने पुलिस ऑफिशियल घायल हुए थे इनमें ज्यादातर को अब अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। उनकी अब ड्यूटी भी लगाई जा रही है।

>> (शेष पेज 06 पर)

आरएएफ पैलेट गन चलाने के आरोपों की जांच करेगी

रैपिड एक्शन फोर्स ने दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पैलेट गन चलाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि RAF यह जांचेगी कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान RAF की टीमों ने क्या कार्रवाई की और किन परिस्थितियों में जवानों पर हमला हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर RAF जवानों की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इनमें कुछ वीडियो में जवानों को बंदूक और लाठी का इस्तेमाल करते तथा लाठीचार्ज करते हुए देखा जा सकता है। वहीं कुछ वीडियो में प्रदर्शनकारियों द्वारा RAF जवानों को घेरकर उन पर हमला करते हुए भी दिखाया गया है।

हिमाचल में चलती कार पर चट्टानें गिरीं, 13 की मौत

गुजरात के नवसारी में बाढ़, हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को उदयपुर-किलाड़ सड़क पर कडू नाला के पास लैंडस्लाइड हो गई। इसकी चपेट में टाटा सूमो टैक्सी आ गई। गाड़ी में 15 लोग सवार थे, 13 की मौत हो गई। उधर गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद, सूरत में पानी भर गया। वाव-थराद जिले में बाजार डूब गए। यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सीतापुर में पानी सड़क पर भर गया। ग्रामीण नाव से आ-जा रहे हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले के पश्चिमी भाग में भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी उफान पर है, जिससे चंदोरी गांव में बाढ़ आ गई है। व्यापक जलभराव से घर और दुकानें जलमग्न हो गई हैं।

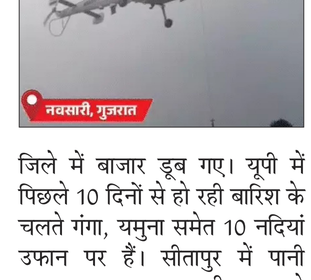

मेरठ में अर्थी निकालकर विरोध, लखीमपुर में एसडीएम को छात्रों ने गुलाब दिए

कॉकरोच पार्टी के समर्थन में वकील-छात्र सड़क पर

जुलूस

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। यूपी में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में शुक्रवार को छात्र और वकील सड़क पर उतर आए हैं। प्रयागराज में वकीलों ने जुलूस निकाला। उन्होंने कहा,'जिन पर लाठियां बरसाई गईं, वे हमारे बच्चे हैं। अब लड़ाई सड़कों पर होगी।

मेरठ में सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रतीकात्मक अर्थी निकाली। पुलिस-कर्मियों ने सपा कार्यकर्ताओं से प्रतीकात्मक अर्थी छीन ली और

लखीमपुर

अपने साथ ले गए। इस दौरान एक सपा कार्यकर्ता सड़क पर लेट गया। पुलिस उसे उठाकर वहां से ले गई।

कानपुर में सपा विधायक ने ढपली बजाकर प्रदर्शन किया। लखीमपुर में छात्र हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने SDM को गुलाब के फूल देकर विरोध दर्ज कराया।

दरअसल, CJP ने देशभर में आंदोलन की अपील की है। इसे देखते हुए प्रदेशभर की पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा- सरकार छात्रों के आंदोलन को उग्र बताने की कोशिश कर रही है। यह उग्र आंदोलन नहीं है, बल्कि युवा रोजगार मांग रहे हैं। पुलिस के डंडे में सरकार का चेहरा दिखता है।

सपा सांसद इकरा हसन बोलीं- सभी लोगों को इस्तीफा चाहिए, हम उस पर अटल

सपा सांसद इकरा हसन ने कहा- इधर-उधर की बाते चल रही हैं। पहले छात्रों की मांग पूरी की जाए। सभी लोगों को इस्तीफा चाहिए, हम उस पर अटल हैं। छात्रों की मांग अटल है। रेप के मामलों में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनें हैं उनमें कितनी कार्रवाई हुई है? कितनी प्रगति हुई है ये भी सोचने की बात है।

अजय राय बोले- शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें

प्रयागराज में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के साथ हुए व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ जैसा व्यवहार किया गया, वह भी बेहद अफसो-सजनक है। हमारे नेता के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, वह ठीक नहीं था। शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दें।

डिंपल यादव बोलीं- शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा- सरकार यह चाहती है छात्रों का जो मुद्दा है, वो खत्म हो जाए। अगर सरकार वास्तव में छात्रों का हित चाहती है, तो उनको NTA को हटा देना चाहिए। बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। यह केवल दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हो रहा है। मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

खीमपुर में छात्र हाथों में तिरंगा और पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा- प्रधानमंत्री पर भरोसा मत कीजिए, वे झूठ बोलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेंगे। ये लोग भगवान राम का पैसा खा गए, फिर भी मोदी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं?

भाजपा नेता ने दवा व्यापारी को चप्पलों से पीटा

अमेठी में मेडिकल स्टोर में घुसकर लात-घूसे बरसाए

तमसा संकेत, एजेंसी

भाजपा नेता, आरोपी

अमेठी जिला। अमेठी में भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष ने मेडिकल स्टोर में घुसकर दवा व्यापारी के साथ मारपीट की। उन्होंने केमिस्ट पर लात-घूसे बरसाए। कुर्सी से उठाकर थप्पड़ मारे और फिर चप्पल से पीटना शुरू कर दिया।

घटना गुरुवार शाम करीब 5:15 बजे मुसवापुर चौराहे की है। इसका 25 सेकेंड का CCTV वीडियो शुक्रवार को सामने आया। वीडियो में भाजपा नेता दवा व्यापारी को लगातार चप्पल से पीटते दिख रहा है। करीब 10 सेकेंड में उसने 7 बार चप्पल से पीटा। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और बीच-बचाव कर व्यापारी को छुड़ाया।

व्यापारी का आरोप है कि उसने भाजपा नेता से दवा के 850 रुपए उधार मांगे थे। इसी बात पर वह भड़क गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

भाजपा नेता ने भी दवा व्यापारी के खिलाफ शिकायत दी है। उनका आरोप है कि वह पिछले तीन महीने से उसी मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे थे, लेकिन दवा से फायदा नहीं हो रहा था। शिकायत करने पर केमिस्ट ने उनके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद विवाद हुआ।

हरदोई के माधौगंज के रहने वाले मुकेश कुमार द्विवेदी सुल्तानपुर में किराए पर रहते हैं। अमेठी के मुंशीगंज क्षेत्र के मुसवापुर चौराहे पर 'मेडिक्स हेल्थकेयर' नाम से उनका मेडिकल स्टोर है।

फास्ट न्यूज

खाद संकट से किसान परेशान

बाराबंकी। बाराबंकी में धान की खेती के महत्वपूर्ण समय में किसानों को यूरिया और डीएपी खाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शुक्रवार को जिले की कई सहकारी समितियों और निजी खाद बिक्री केंद्रों पर सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें देखी गईं। कई किसानों ने आरोप लगाया कि घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे धान की फसल प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है।

निरीक्षण करने पहुंचे अफसर को थप्पड़ मारे

गोरखपुर । गोरखपुर के सिंचाई विभाग के कार्यालय में इंजीनियर की पिटाई कर दी गई। वह कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी बीच, निलंबित क्लर्क, सहायक अभियंता और एक युवक वहां पहुंच गए। तीनों ने उन्हें घेर लिया और थप्पड़ बरसाए। इस दौरान निलंबित क्लर्क ने कहा, 'पिस्तौल निकालो, आज इसी को मार देते हैं। इसे छोड़ूंगा नहीं।

करीब 20 मिनट तक कार्यालय में मारपीट-हंगामा चलता रहा। वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। घटना गुरुवार दोपहर 1 बजे की है, इसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया।

शिव मंदिरों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करें

बाराबंकी। बाराबंकी में सावन मास के दौरान शिव मंदिरों और मेला स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक हुई।

70 साल के कारोबारी की छात्र ने हत्या की

बाइक खरीदने के लिए एक लाख उधार लिए थे

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर । गोरखपुर में 10वीं के छात्र ने 70 साल के सराफा कारोबारी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, 19 साल के छात्र ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर कारोबारी की गर्दन पर चाकू से 6 वार किए। इसके बाद दोनों हाथ पकड़कर शव को 500 मीटर तक घसीटा और राप्ती नदी में फेंककर फरार हो गए।

पुलिस के मुताबिक, छात्र ने कारोबारी से एक लाख रुपए उधार लिए थे। रुपए न लौटाने पड़ें, इसलिए उसने लिफ्ट देने के बहाने कारोबारी को बाइक पर बैठाया। फिर भगवान राम के दर्शन कराने के बहाने सुनसान जगह ले गया और वारदात को अंजाम दिया।

ग्रामीणों ने शव को नदी में उतराता देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले

तो छात्र कारोबारी को बाइक पर बैठाकर ले जाता दिखा। गुरुवार रात 10 बजे पुलिस ने आरोपी छात्र प्रिंस, उसके ममेरे भाई अंशू (18) और एक किशोर को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी फरार है।

एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि बांसगांव क्षेत्र के धस्का भटास के रहने वाले रामलाल वर्मा की कटरा मलांव में सोने-चांदी की दुकान थी। आरोपी प्रिंस से उनका पुराना परिचय था। वह अक्सर रामलाल को बाइक से दुकान तक छोड़ता और घर भी पहुंचाता था, इसलिए परिवार के लोग भी उसे पहचानते थे।

यूपी में रोड पर चली नाव, डैम ओवरफ्लो

4 नदियां खतरे के निशान के पार, मगरमच्छ गांव में घुसा, 5 शहरों में बारिश

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी, प्रयागराज। यूपी में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। गंगा-यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोनभद्र में कनहर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके 3 गेट खोल दिए गए हैं। सीतापुर में बनबसा, गिरिजा और घाघरा बैराजों से 3.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शारदा और घाघरा नदियां उफान पर हैं। दोनों का पानी गांवों में घुस गया है। एक गांव में कच्ची रोड के ऊपर पानी बह रहा है। ग्रामीण नाव से आ-जा रहे हैं।

बागपत और नोएडा में हिंडन, बदायूं में गंगा, अयोध्या, गोंडा और बलिया में घाघरा, जबकि कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लखीमपुर खीरी के एक गांव में मगरमच्छ सड़क पर दौड़ता नजर आया। बस्ती में सरयू

सोनभद्र

नदी के किनारे तेजी से कटान हो रहा है। कई पेड़ नदी में समा गए। शुक्रवार सुबह लखनऊ, गोंडा, गाजियाबाद में बारिश हुई। दोपहर को मेरठ और बरेली में बारिश हुई। आज प्रदेश के 54 जिलों में बारिश का अलर्ट है। गुरुवार यानी कल प्रदेश के 42 जिलों में औसतन 2.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा 27 मिमी बारिश इटावा में हुई।

सीएम योगी ने अफसरों को फील्ड में उतरने के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा- अफसर बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करें। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया-मानसून रेखा का दक्षिण की ओर खिसकने और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कमजोर होने से अगले 3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मानसूनी सक्रियता फिलहाल पश्चिम-मध्य भारत की तरफ शिफ्ट हो गई है। 3-4 दिन बाद हालात बदलेंगे। 26 और 27 जुलाई से मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा। अच्छी बारिश होगी।

वाराणसी में गंगा का जलस्तर 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा

वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस समय गंगा का जलस्तर 61.06 मीटर दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3.2MM बारिश हुई। शुक्रवार दोपहर को गेरठ में अचानक मौसम बदल गया और बारिश शुरू हो गई। यहां हल्की हवा भी चल रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे दिन मौसम ऐसा ही रहेगा।

सीतापुर में नदियां का पानी गांव में घुस गया है। एक गांव में कच्ची रोड के ऊपर पानी बह रहा है। ग्रामीण नाव से आ-जा रहे हैं।

> शुक्रवार दोपहर को बरेली में बारिश शुरू हो गई। यहां हल्की हवा भी चल रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। रुक-रुककर हल्की बारिश होगी।

बाराबंकी में दो बार अबॉर्शन, चलती कार में दोस्त से जबरन शादी कराई

सिपाही ने नाबालिग से रेप कर धर्मांतरण कराया

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। बारांबकी में एक सिपाही ने 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप किया। लड़की गर्भवती हो गई तो दवा खिलाकर उसका अबॉर्शन करा दिया। मामला बढ़ा तो मौलाना की मदद से चलती कार में दोस्त के साथ उसका निकाह करवा दिया। नाबालिग की मां ने गुरुवार रात एसपी विजय वर्गीय से मुलाकात करके मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से सिपाही और उसके साथी मां-बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एसपी के निर्देश पर फतेहपुर कोतवाली में सिपाही, मौलाना समेत 4 नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता का मेडिकल

आसिफ, आरोपी सिपाही

टेस्ट कराया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बेटी के न मानने पर आसिफ ने सऊदी में रह रहे जावेद को मेरी बेटी का नंबर दे दिया। वह फतेहपुर के ही बसारा गांव का रहने वाला है। जावेद ने मेरी बेटी को धर्मांतरण के लिए उकसाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मेरी बेटी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती बढ़ा ली। उसका ब्रेनवाश कर धर्मांतरण के लिए तैयार कर लिया। 2 जनवरी, 2026 को जावेद सऊदी से लौटा और बेटी को फुसलाकर अपने साथ ले गया। जहां एक कमरे में उसने बेटी के साथ रेप किया। उसे कुरान पढ़ाकर बताया कि मुस्लिम धर्म सबसे ऊपर होता है। इसके बाद से जावेद और आसिफ मिलकर बेटी के साथ रेप करने लगे।

कोतवाल अमित कुमार ने बताया-पीड़िता और उसकी मां की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों और आठ अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है ।

मां बोली- सिपाही ने बेटी को पैसे का लालच देकर फंसाया

नाबालिग की मां ने पुलिस को बताया- मेरे पति की कई साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। मैं अपनी 16 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में रहती हूं। बेटी ने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई है।

मेरी बेटी का साल 2024 फतेहपुर कोतवाली में तैनात सिपाही आसिफ से संपर्क हुआ। आसिफ ने उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। कई बार फोन पर इसके लिए दबाव बनाया। उसने बेटी की गरीबी हालत का फायदा उठाकर पैसों का लालच दिया। उसे धर्मांतरण करने के लिए उकसाने लगा।

'स्वच्छ भारत' का ढांचा ध्वस्त आरआरसी सेंटर बना खंडहर

लाखों का बजट खा गई दीमक, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा मंसूरपुर गिरन्ट का आर .आर.सी.सेंटर

तमसा संकेत, संवाददाता

कटेहरी/अंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 'स्वच्छ भारत मिशन' को ग्राम पंचायत मंसूरपुर गिरन्ट, ब्लॉक कटेहरी में भ्रष्टाचार की दीमक चाट गई। लाखों रुपये की लागत से बना आर.आर.सी. सेंटर आज खंडहर में तब्दील होकर सरकारी सिस्टम की पोल खोल रहा है।

'एक कदम स्वच्छता की ओर' का नारा लिखी दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन सेंटर का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। टीन शेड उखड़कर लटक रहे हैं, लोहे के एंगल टूटे पड़े हैं, और चारों तरफ झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। आलम ये है कि कूड़ा प्रबंधन के लिए बना ये सेंटर खुद कूड़े के ढेर में बदल गया है। ग्राम पंचायत मंसूरपुर गिरन्ट में स्वच्छ भारत मिशन के तहत RRC सेंटर बनवाया गया था लागत करीब 4-5 लाख बताई जा रही है।

उद्देश्यः सूखा-गीला कचरा अलग

कर खाद बनाना, गांव को कचरा मुक्त करना हकीकतः बनने के 1 साल में ही सेंटर धराशायी, एक दिन भी काम नहीं हुआ । ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री लगाई गई। सरिया की जगह बांस, सीमेंट में बालू ज्यादा, और फाउंडेशन तो नाम का ही था। पेमेंट पूरा निकाल लिया गया, लेकिन पहली बरसात में ही सेंटर 'ताश के पत्तों' की तरह बिखर गया।

तत्कालीन ग्राम प्रधान बिना गुणवत्ता जांच के पेमेंट कैसे रिलीज हुआ?

सचिव व जेई एमआई मौके पर निरीक्षण क्यों नहीं किया?

खंड विकास अधिकारी कटेहरी जियो टैग फोटो लगाकर फर्जी रिपोर्ट कैसे भेजी गई?

सरकार पैसा भेजती है, पर यहाँ 'बंदरबांट' हो जाता है। RRC सेंटर के नाम पर सिर्फ कमीशन खाया गया। अब कचरा कहाँ फेंकें? गांव में फिर गंदगी फैल रही है' - _नाम न छापने की शर्त पर एक ग्रामीण जिलाधिकारी से मांग

इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर भ्रष्टाचार में लिप्त प्रधान, सचिव, जेई और ठेकेदार पर FIR दर्ज हो। सेंटर का पुनर्निर्माण कराकर दोषियों से रिकवरी की जाए।

सरयू-घाघरा का जलस्तर घटा बाढ़ पीड़ितों का भय बरकरार

एसडीएम ने किया बांध का निरीक्षण

तमसा संकेत, संवाददाता

सूरतगंज (बाराबंकी)। हेतमापुर स्थित सरयू-घाघरा नदी के जलस्तर में शुक्रवार को कुछ गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर था, जो शुक्रवार को घटकर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया। जलस्तर में कमी आने के बाद भी तटवर्ती गांवों के लोगों में चिंता बरकरार है, ऐसे में अब भी सुंदरनगर गांव बाढ़ के पानी से चारों ओर घिरा हुआ है और लोग उसी के बीच अपना जीवन यापन कर रहे है।

शुक्रवार को रामनगर की उपजि-लाधिकारी आकांक्षा गुप्ता ने तहसील प्रशासन की टीम के साथ हेतमापुर बाढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, नदी के बहाव तथा संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को

निर्देश दिए कि नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखें। उपजिलाधिकारी ने अफवाहों पर ध्यान न देने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि नदी का जलस्तर बढ़ते देख सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग, पीएससी, सिंचाई विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से सरयू-घाघरा नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इससे सुंदर-नगर, बेलहारी, भलाईपुर, बाबापुरवा, ललपुरवा, कोड़री, सरसंडा सहित कई तटवर्ती गांवों के लोग बाढ़ की आशंका को लेकर चिंतित हैं। और बाढ़ पीड़ित बांध पर जुग्गिया बना रखे है। प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान मौसम में कभी भी बदलाव हो सकता है।

दुर्घटना : मेरठ में बारिश के बीच हादसा, 11 श्रद्धालु झुलसे, 2 हजार लोग मौजूद थे

जगन्नाथ रथ हाईटेंशन लाइन से टकराया, युवक की मौत

तमसा संकेत, एजेंसी

मेरठ। मेरठ में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के दौरान रथ 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से छू गया। करंट लगने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई। 11 लोग झुलस गए।

हादसा परीक्षितगढ़ कस्बे में हुआ। बारिश के बीच यह रथयात्रा निकाली जा रही थी। इसमें करीब 2 हजार श्रद्धालु शामिल थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करंट उतरते ही रथ पर सवार कई लोग नीचे गिर पड़े। मौके पर चीख-पुकार मच गई। भगदड़ जैसे हालात बन गए। श्रद्धालु जान बचाने के लिए

सचिन
मृतक

इधर-उधर भागने लगे। हादसे में परीक्षितगढ़ का रहे वाला सचिन (30) गंभीर रूप से झुलस गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, झुलसे 11 श्रद्धालुओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सचिन मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाता था। उसके पिता नंदकिशोर भी मजदूरी करते हैं। परिवार में मां, छोटा भाई विशाल और दो बहनें प्राची व विशाखा हैं। सचिन की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। झुलसे लोगों में प्रियांशु, विवेक, मनीष निवासी औरंगाबाद, शिवम, यश, पीहू निवासी परीक्षितगढ़, निमेष निवासी अहमदपुरी, महाराज भरतदास लखीमपुर खीरी, राजेश मिश्रा समेत 11 हैं।

गुरुवार शाम को हुआ था कथा का समापन

परीक्षितगढ़ कस्बे के ओम पब्लिक स्कूल में जगन्नाथ भगवान की शोभायात्रा और कथा का कार्यक्रम था। पांच दिन पहले नगर में भगवान जगन्नाथ की धूमधाम से शोभायात्रा निकाली गई थी। इसके बाद महाराज रोहित रिसालिया वृंदावन द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा था। गुरुवार शाम कथा का समापन हो गया। शुक्रवार दोपहर को भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा बैंड बाजों के साथ नगर में निकाली गई। यात्रा शुरू होते ही यह हादसा हो गया।

बिना पूजा अर्चना शुरू कर दी रथ यात्रा

रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान हो चुके थे। पूजा अर्चना की तैयारी चल रही थी, ताकि विधिवत रथयात्रा शुरू हो सके। इसी दौरान कुछ लोग बारिश शुरू होते ही रथ की रस्सी को खींचकर ले जाने लगे। कुछ श्रद्धालुओं ने इसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वह रजवाहे की पटरी की तरफ रथ को लेकर जाने लगे। यहां रथ की चोटी ऊपर से गुजर रही 11000 की हाई टेंशन लाइन में छू गई और करंट उतर आया।

जिला महिला अस्पताल में बंद मिली लिफ्ट, अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर महिला आयोग की नजर

महिला अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर और जिला कारागार का किया निरीक्षण

दौरा

बृजेंद्र वीर सिंह

तमसा संकेत, अंबेडकरनगर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने शुक्रवार को जनपद के दौरे के दौरान जिला महिला चिकित्सालय, वन स्टॉप सेंटर और जिला कारागार का निरीक्षण किया। इसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की समीक्षा की और जनसुनवाई में आई शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। दौरे के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और लैपटॉप भी वितरित किए गए। दौरे की शुरुआत जिला महिला चिकित्सालय के निरीक्षण से हुई। अध्यक्ष ने दवा वितरण काउंटर, पर्चा काउंटर, वजन जांच मशीन, रैंप, प्रसूति वार्ड, आपात-कालीन कक्ष और अस्पताल के अभिलेखों की विस्तार से जांच की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की लिफ्ट बंद मिली। इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लिफ्ट संचालक की तैनाती नहीं होने के कारण सेवा बाधित है। अध्यक्ष ने इस व्यवस्था को जल्द बहाल कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की स्थिति की जानकारी ली। भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता, दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टरों के व्यवहार के बारे में भी फीडबैक लिया।

कन्या जन्मोत्सव में शामिल हुईं

अस्पताल परिसर में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। इस दौरान अस्पताल में जन्मी नवजात बालिकाओं और उनके माता-पिता को सम्मानित किया गया। उन्हें बेबी किट और फल वितरित किए गए। अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों और उनके तीमारदारों को भी फल दिए गए।

अस्पताल के बाद अध्यक्ष ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर वहां संचालित सेवाओं की जानकारी ली। इसके बाद जिला कारागार पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कारागार परिसर में उन्होंने वृक्षारोपण किया और वहां स्थापित दो नए पावरलूम का उद्घाटन कर उन्हें औपचारिक रूप से समर्पित किया।

जनसुनवाई में 18 महिलाओं की शिकायतें

सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा की। इसके बाद जनसुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न से संबंधित 18 शिकायतों की सुनवाई की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बिजली बिल में बढ़े भार के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूली का आरोप

उपभोक्ताओं ने उठाए सवाल बिना सूचना भार बढ़ाने का दावा

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के विद्युत बिल में बढ़े हुए भार के नाम पर अतिरिक्त शुल्क जोड़ने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के कनेक्शन का भार बढ़ाया गया और इसके बाद सिक्योरिटी राशि के नाम पर अतिरिक्त धनराशि बिलों में जोड़ दी गई। उपभोक्ताओं के अनुसार, जून और जुलाई माह के बिजली बिलों में बढ़े हुए भार के आधार पर अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया है। आरोप है कि यह राशि सिक्योरिटी के रूप में ली जा रही है, लेकिन इसके बदले उपभोक्ताओं को अलग से कोई रसीद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग की ओर से भार बढ़ाने की प्रक्रिया की जानकारी पहले नहीं दी गई। इसके बाद बिल में अचानक अतिरिक्त राशि जुड़ने से लोगों में असमंजस की स्थिति है। कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि बढ़े हुए भार के नाम पर सिक्योरिटी के रूप में 1200 रुपये से अधिक की अतिरिक्त धनराशि ली जा रही है। इस मामले को लेकर उपभोक्ताओं ने विभागीय प्रक्रिया और जानकारी देने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसी भी अतिरिक्त शुल्क की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। मामले को लेकर जनपद के एसी रजनीश श्रीवास्तव से जानकारी लेने का प्रयास किया गया। उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देने के बजाय अन्य विभागीय अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी। फिलहाल बिजली विभाग की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों और लगाए गए आरोपों पर विभाग का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली से जुड़े शुल्क और भार परिवर्तन की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की अतिरिक्त वसूली से पहले उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए और भुगतान से संबंधित स्पष्ट रसीद उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

फास्ट न्यूज

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के साक्षात्कार में प्रमाण पत्र सत्यापन पर सवाल

अंबेडकरनगर। जिला उद्योग कार्यालय में संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत आयोजित साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर सवाल उठे हैं। आरोप है कि दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य एक कथित निजी कर्मचारी से कराया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में जिला उद्योग कार्यालय की ओर से आधिकारिक पुष्टि या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पेपर लीक के विरोध में सपा युवा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

अंबेडकरनगर। पेपर लीक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अकबरपुर के पटेल तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। सपा यूथ ब्रिगेड के नेता महेंद्र यादव के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंकने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस की तत्परता के चलते पुतला दहन नहीं हो सका। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सदर कोतवाल संतोष सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के हाथ से पुतला छीन लिया ।

आयकर विभाग की संगोष्ठी

अंबेडकरनगर। टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रहण) के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित लोहिया भवन में संगोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम में सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, कर सलाहकारों और विभिन्न टीडीएस कटौतीकर्ताओं को नियमों के पालन, समय पर कर जमा करने और ई-फाइलिंग की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई।

भाजपा की बैठक में डीएलपी अभियान और संगठनात्मक कार्यक्रमों की बनी रणनीति

बूथ स्तर तक पहुंच बढ़ाने पर जोर, गुरु रविदास जयंती और 'मन की बात' कार्यक्रम की तैयारियों पर हुई चर्चा

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय अटल भवन में गुरुवार को संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएलपी अभियान, दीर्घकालिक संगठनात्मक अभियानों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के सफल आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी रहे। अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल देव ने की।

बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है और बूथ स्तर के कार्यकर्ता इसकी प्रमुख ताकत हैं। उन्होंने कहा कि डीएलपी अभियान संगठन को और मजबूत बनाने का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर-घर जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही संत गुरु रविदास के विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए जयंती कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को प्रत्येक बूथ पर अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता के साथ सुनने की अपील भी की। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल देव ने कहा कि संगठन की ओर से दिए गए प्रत्येक कार्यक्रम को कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ पूरा करें।

कब्र से लाश निकली तो बाप ने खा लिया जहर, 'मैडम राज' में खुदी कब्र

सच सामने आते ही आरोपी पिता ने की खुदकुशी की कोशिश

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। रामपुर बनेथू गांव में माँ की मौत के मामले में सनसनीखेज मोड़ आ गया है। एक तरफ प्रशासन ने 11 दिन बाद कब्र खोदकर शव बाहर निकलवाया, तो दूसरी तरफ शव निकलते ही आरोपी पिता ने जहर खा लिया।

जिलाधिकारी ईशा प्रिया के आदेश पर शुक्रवार को तहसीलदार अकबरपुर व पुलिस बल की मौजूदगी में जब महिला का शव कब्र से निकाला जा रहा था, उसी वक्त बेटे के आरोपों से घिरे पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे आनन-फानन में एम्बुलेस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया! बेटे आकाशा ने 13 जुलाई की रात पिता पर माँ की हत्या का आरोप लगाया था।

उसका कहना था कि बिना पोस्टमार्टम के ही शव दफना दिया गया। 11 दिन थाने से कलेक्ट्रेट तक भटकने के बाद जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से कब्र खोदी गई।

मजिस्ट्रेट की निगरानी व वीडियोग्राफी के बीच कब्र की खुदाई हुई

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया इसी दौरान आरोपी पिता के जहर खाने की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया

माँ की हत्या के बाद सबूत मिटाने को शव दफना दिया। अब जब कब्र खुदी और सच सामने आने वाला था तो बाप ने डर के मारे जहर खा लिया - आकाशा

जिलाधिकारी के एक्शन से हिला सिस्टम सोशल मीडिया पर खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया था। सूत्रों के अनुसार अब आरोपी के जहर खाने के बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है।

खाद दुकानों पर कृषि विभाग की छापेमारी, तीन को नोटिस और एक लाइसेंस निलंबित

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग ने गुरुवार को जिलेभर में उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कुल 267 खाद दुकानों का निरीक्षण किया। अनियमितताएं मिलने पर तीन प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि एक दुकान का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। कृषि विभाग की संयुक्त टीम में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक (यूपी), जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक और अन्य अधिकारी शामिल रहे। टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर उर्वरक बिक्री, उपलब्धता और अभिलेखों की जांच की। उप कृषि निदेशक डॉ. अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों पर अनियमितताएं मिलीं। इसके बाद मानु उर्वरक भंडार, पहितीपुर, धर्मेन्द्र प्रकाश शुक्ला, आदमपुर तिन्दोली और भैयालाल सोनी, महड़ुआ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं जांच में मिली कमियों के आधार पर किसान खाद भंडार, आदमपुर बिंदौली का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

कृषि विभाग ने बताया कि जुलाई माह तक जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार सहकारिता और निजी क्षेत्र में वर्तमान में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और एमओपी का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

267 उर्वरक प्रतिष्ठानों की हुई जांच, विभाग ने बताया- जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडार उपलब्ध

2 सुपर जोन में बांटा जिला, 78 सेक्टर संभालेंगे सुरक्षा

कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस का मेगा प्लान

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। सावन माह में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अंबेडकरनगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और यात्रा मार्गों की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे जिले को दो सुपर जोन, आठ जोन और 78 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। हर सेक्टर में दारोगा और पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।

सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई से होगी। इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। अयोध्या स्थित सरयू नदी से जल लेकर श्रद्धालु जिले के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कांवड़ मार्गों, नदी घाटों और प्रमुख धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा का पूरा खाका तैयार किया है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिले के 179 शिव मंदिरों, 37 नदी घाटों, 15 मेला स्थलों और 53 शोभायात्राओं के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सरयू नदी और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 44 गोताखोर और 30 नाविक तैनात किए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाने के लिए नदी घाटों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले के 72 पड़ाव स्थलों पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इन स्थानों पर छह एंबुलेंस की व्यवस्था रहेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिले में सात बैरियर लगाए गए हैं। इन बैरियरों पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार वाहनों का रूट डायवर्जन भी किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि यात्रा के दौरान अफवाह फैलाने या भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

कांवड़ मार्गों पर पुलिस की पैनी नजर

कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने जिले की 399 कांवड़ समितियों और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। इसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को लेकर निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा कांवड़ मार्गों पर स्थित मांस-मछली की दुकानों और ढाबों का भी निरीक्षण किया गया। संबंधित लोगों को यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

> **कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, पावर कारपोरेशन और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाया गया है। बिजली, सड़क, सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विभागों को जिम्मेदारी दी गई है।**

ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर 247 स्कूलों को नोटिस

मान्यता वापसी की चेतावनी, डीआईओएस ने प्रधानाचार्यों को दिए निर्देश

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। जिले के 247 स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों पर विभागीय निर्देशों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज नहीं करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने सभी संबंधित विद्यालयों को नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्देशों का पालन नहीं होने पर मान्यता वापस लेने की संस्तुति की चेतावनी दी गई है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव के निर्देश के अनुसार सभी स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यालयों में छात्रों की संख्या और नियमित उपस्थिति की निगरानी को बेहतर बनाना है।

विभागीय निर्देश जारी होने के बाद भी जिले के 247 स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों ने अब तक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की है। इसके चलते इन विद्यालयों की उपस्थिति पोर्टल पर शून्य दिखाई दे रही है। विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सभी विद्यालयों को नोटिस भेजा है। डीआईओएस डॉ. कौस्तुभ सिंह ने विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित करने और टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार गठित टीम संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से संपर्क करेगी और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित कराएगी। विभाग की ओर से विद्यालयों को निर्धारित व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा गया है। डीआईओएस डॉ. कौस्तुभ सिंह ने कहा है कि नोटिस के बाद भी यदि विद्यालयों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की तो संबंधित प्रधानाचार्य और नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

किसानों को नई खेती की तकनीक का प्रशिक्षण

18 फार्म स्कूलों पर शुरू हुआ खरीफ सत्र

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। खरीफ सीजन 2026-27 में किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ने के लिए अंबेडकरनगर में फार्म स्कूल कार्यक्रम शुरू हो गया है। जिले के सभी विकास खंडों में चयनित 18 फार्म स्कूलों पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कृषि विभाग के अधिकारी और नामित नोडल अधिकारी किसानों को नई कृषि तकनीकों, उन्नत बीज, उर्वरक प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं।

कृषि विभाग के अनुसार प्रत्येक विकास खंड से दो प्रगतिशील किसानों का चयन कर उनके खेत को फार्म स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। इन खेतों पर खेती की नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है। फसल की चार अलग-अलग अवस्थाओं में 25-25 किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आधुनिक खेती की विधियों से अवगत कराया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान फार्म स्कूल में तैयार फसल की उपज का आकलन भी किया जाता है, ताकि नई तकनीकों के परिणाम किसानों के सामने स्पष्ट हो सकें। वित्तीय वर्ष 2026-27 के खरीफ सत्र के लिए जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने जिले के सभी 18 फार्म स्कूलों में प्रशिक्षण की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। ये अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होकर किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं और नई तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं।

निर्देश : प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी, राहत-बचाव की तैयारियां पूरी

सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। सरयू (घाघरा) नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद अंबेडकरनगर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, लखनऊ से जारी बाढ़ अलर्ट के बाद संभावित प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियां पूरी करने के साथ सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार बाराबंकी जनपद स्थित एल्गिन ब्रिज पर सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान 106.070 मीटर को पार कर 106.130 मीटर दर्ज किया गया है। यानी नदी का जलस्तर खतरे के स्तर से 0.060 मीटर ऊपर पहुंच गया है। विभाग के अनुसार नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति में है। जिलाधिकारी ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें। लोगों से नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की गई है। साथ ही जलमग्न सड़कों और पुलों को पार करने से बचने को कहा गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी और जलभराव वाले स्थानों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, आवश्यकता पड़ने पर चिन्हित सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचने, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने तथा खुले बिजली के तारों और जलमग्न विद्युत उपकरणों से दूर रहने की अपील की है। इसके अलावा आवश्यक दवाइयां, पेयजल और सूखा खाद्यान्न पहले से सुरक्षित रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन, पुलिस या संबंधित नियंत्रण कक्ष को सूचना देने को कहा गया है।

तहसीलों से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक सभी एजेंसियां सतर्क

बाढ़ अलर्ट के बाद जिले की सभी संबंधित तहसीलों के साथ पुलिस, सिंचाई, राजस्व, स्वास्थ्य, पशुपालन और अन्य विभागों को सतर्क कर दिया गया है। बाढ़ संभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। स्थानीय प्रशासन को संवेदनशील गांवों में नियमित भ्रमण करने और हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली गई हैं। सभी विभागों के बीच समन्वय बनाकर हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

टांडा में 'शिव शक्ति होलसेल बाजार' का शुभारंभ

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया उद्घाटन

तमसा संकेत, संवाददाता

अंबेडकरनगर। टांडा में गुरुवार को 'शिव शक्ति होलसेल बाजार' का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत तैयार इस एमओयू आधारित प्रोजेक्ट के शुभारंभ कार्यक्रम में जिलाधिकारी ईशा प्रिया सहित कई जनप्रतिनिधि, व्यापारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले गोहन्ना बाईपास पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण समिति के सदस्य शुभम अग्रहरी और भाजपा टांडा नगर अध्यक्ष तेजस्वी जायसवाल ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद काफिला कार्यक्रम स्थल कश्मीरिया चौराहे पहुंचा।

कार्यक्रम स्थल पर नौ दिनों से चल रहे सत चंडी महायज्ञ के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और शंख-मृदंग की ध्वनि के बीच उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान 11 पंडितों ने मंत्री से आरती कराई। इसके बाद उन्होंने वैश्य समाज और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के स्वागत मंच को स्वीकार किया। 'शिव शक्ति होलसेल बाजार' के संचालक संतोष अग्रवाल ने कार्यक्रम में बाजार की योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमओयू के माध्यम से जल्द ही 50 से 100 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। साथ ही टांडा में तैयार होने वाले उत्पादों को निर्यात बाजार तक पहुंचाने की योजना भी बताई।

सम्पादकीय

गतिरोध की राजनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के आरोपितों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाने की जो घोषणा की, वह उन्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अच्छा होता कि इस विषय पर वे समय रहते देश को सीधे तौर पर संबोधित करते। इससे लोगों और खासकर छात्रों के इस भरोसे को बल मिलता कि सरकार इस मामले के दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के प्रति सचमुच प्रतिबद्ध है।

जैसे नीट मामले में प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर वक्तव्य आने में देरी हुई, वैसे ही इस प्रकरण को लेकर धरने पर बैठे समूह काकरोच जनता पार्टी से संपर्क-संवाद करने में भी। इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल सीजेपी के संसद मार्च में हिंसा हुई, बल्कि राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों को भी मौका मिल गया। इसके पहले मौका उन्हें भी मिला, जो सीजेपी के संसद मार्च में शामिल होकर अराजकता फैलाने का इरादा रखते थे। वे अपने इरादे में इसलिए सफल रहे, क्योंकि पुलिस न तो भीड़ का अनुमान लगा सकी और न ही उसकी उग्रता का। पुलिस के पास शायद अचानक उमड़ी और संसद भवन जाने को उतावली भीड़ से निपटने की कोई ठोस रणनीति या तैयारी नहीं थी। इसके अभाव में ही उसे सख्ती का सहारा लेना पड़ा, जो स्वाभाविक रूप से एक मुद्दा बन गई है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और इसीलिए उसने यह मांग रख दी है कि संसद तब चलेगी, जब पुलिस की सख्ती पर प्रधानमंत्री माफी मांगने के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से त्यागपत्र लेंगे।

विपक्षी दलों जैसा रवैया सीजेपी ने भी अपना लिया है। वह अपनी शर्तों के साथ-साथ अपने बताए ठिकाने पर सरकार से बात करने पर अड़ गई है। अब उसके लोग किसी मंत्री के घर या दफ्तर बात करने के लिए तैयार नहीं। यह हठधर्मिता है। इससे विचित्र और कुछ नहीं हो सकता कि गतिरोध इस पर कायम हो जाए कि बात कहां होनी चाहिए? कहना कठिन है कि उसके और सरकार के बीच का गतिरोध कैसे टूटेगा?

लगता है जैसे विपक्ष की दिलचस्पी संसद चलने देने में नहीं, वैसे ही सीजेपी की भी पहली प्राथमिकता परीक्षा व्यवस्था में सुधार की नहीं दिखती। उसका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र दिखता है। इस हिसाब से तो उन सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के त्यागपत्र मांगे जाने चाहिए, जहां पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक हुए हैं।

छात्र हित के नाम पर की जा रही इस राजनीति के बीच सरकार को यह सचमुच सुनिश्चित करना चाहिए कि पेपर लीक के दोषियों को सच में समय पर कठोर दंड मिले। इसके लिए सीबीआई को भी तत्परता दिखानी होगी। यह शुभ संकेत नहीं कि 2024 के नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपित के खिलाफ सीबीआई को कोई प्रमाण नहीं मिले।

जल संकट का असंतुलित प्रबंधन अस्तित्व पर मंडराता खतरा

> भारत की कृषि व्यवस्था आज भी लगभग 80 प्रतिशत मीठे जल का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से धान, गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जा रही हैं जहां जल संसाधन सीमित हैं।

जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना असंभव है, फिर भी विडंबना यह है कि जिस जल को हमारी संस्कृति ने देवत्व प्रदान किया, उसी जल के प्रति हमारा व्यवहार सबसे अधिक लापरवाह रहा है। आज देश और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में जल संकट प्रमुख बन चुका है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तन और वर्षाजल के समुचित प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को भयावह बना दिया है। यदि समय रहते चेतना नहीं जागी तो आने वाले वर्षों में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हाल के शोध इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उत्तर भारत का भूजल भंडार लगभग 450 घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग 37 गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है। इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है। परिणामस्वरूप खेतों को पहले की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा कम होती है और सिंचाई की मांग बढ़ती है, तब किसान भूजल पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि भूजल का पुनर्भरण कम और दोहन अधिक हो रहा है। आज भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर वर्ष नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के कई हिस्से इस संकट की चपेट में हैं। अनेक स्थानों पर सैकड़ों फीट गहराई तक बोरवेल खोदने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में हैंडपंप सूख चुके हैं और शहरों में टैंकर संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि यदि हमने अपनी जल नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में पानी का संकट भोजन के संकट में भी बदल सकता है। मुफ्त बिजली और सस्ते पानी की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है। जल का मूल्य शून्य समझे जाने के कारण उसका संरक्षण भी नहीं हो पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि नीति को जल उपलब्धता के अनुरूप बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संकट केवल खेती तक सीमित नहीं है। उद्योगों, महानगरों और बढ़ते शहरी विस्तार ने भी भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है। बड़े-बड़े भवनों, कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल सीधे नालों में बह जाता है। यदि प्रत्येक भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाए तो लाखों लीटर पानी हर वर्ष धरती के भीतर पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक राज्यों में कानून तो बने, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो पाया। जल संकट का एक और गंभीर पक्ष जल प्रदूषण है। देश की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कचरे और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। जब नदियों और तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। इसलिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी की जीवनरेखा है। यदि नदियां स्वस्थ रहेंगी तो भूजल भी समृद्ध होगा। आज आवश्यकता केवल नई परियोजनाओं की नहीं, बल्कि जल संस्कृति के पुनर्जागरण की है। भारत में कभी तालाब, बावड़ियां, जोहड़, कुंड और पारंपरिक जल संरचनाएं गांवों की पहचान होती थीं। वे वर्षा के जल को रोककर भूजल को समृद्ध बनाती थीं। आधुनिक विकास की दौड़ में इन जल स्रोतों को या तो नष्ट कर दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। यदि इन पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन किया जाए तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। घरों में पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना, वर्षाजल संचयन अपनाना, रिसाव ठीक कराना, कम पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना और बच्चों में जल संरक्षण के संस्कार विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार प्रतिदिन कुछ लीटर पानी भी बचाए तो राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लीटर जल की बचत संभव है। सरकार को भी जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। प्रत्येक जिले के लिए भूजल बजट तैयार किया जाए, भूजल दोहन पर वैज्ञानिक नियंत्रण हो, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों-ड्रिप और स्प्रिंकलर-को व्यापक प्रोत्साहन मिले तथा ऐसे कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करे। साथ ही जल शिक्षा को विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जल के महत्व को केवल पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में भी समझ सके।

भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल बचेगा? यदि आज भी हमने जल को केवल उपभोग की वस्तु समझा तो आने वाले वर्षों में जल के लिए संघर्ष, पलायन और सामाजिक असंतोष बढ़ना स्वाभाविक होगा। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आएगा। इसलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति का भी प्रश्न है। आज समय की पुकार है कि 'जल बचाना ही भविष्य बचाना है।' हमें बदलती जलवायु के अनुरूप अपनी नीतियों, कृषि प्रणाली और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। वर्षा की प्रत्येक बूंद को धरती में उतारना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल अनुशासन को जन-आंदोलन बनाना ही इस संकट का सबसे प्रभावी समाधान है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, किसान, उद्योग, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर इस दिशा में संकल्पबद्ध प्रयास करें तो जल संकट को अवसर में बदला जा सकता है।

ललित गर्ग

पिछले एक दशक ...

कुमार कृष्णन

जब युवा सवाल बन जाते हैं

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं होती कि सत्ता बहुत शक्तिशाली हो जाती है; वह तब पैदा होती है, जब समाज प्रश्न पूछना छोड़ देता है। नागरिकों की चुप्पी, विश्वविद्यालयों का मौन और युवाओं का केवल निजी सफलता तक सीमित हो जाना किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होता। इसके विपरीत, जब युवा व्यवस्था से जवाब मांगते हैं, तब वह केवल विरोध नहीं होता; वह लोकतंत्र की आत्मा के भीतर उठती नई हलचल का संकेत होता है।

देश में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और रोजगार के प्रश्नों को लेकर उभरे छात्र-युवा आंदोलन को इसी व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। इसे केवल किसी एक परीक्षा, किसी एक पेपर लीक या किसी एक मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित कर देना उसकी प्रकृति को छोटा कर देना होगा। यह उस पीढ़ी की बेचैनी है जिसने वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, रोजगार की अनिश्चितता झेली और अब अपनी मेहनत से अधिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए विवश हो रही है।

दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन कुछ ही दिनों में अनेक राज्यों तक फैल गया। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई ने इस बहस को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया।

लाठीचार्ज, आँसू गैस, घायल छात्र और तनावपूर्ण हालात ने एक मूलभूत प्रश्न सामने रखा—क्या लोकतंत्र में असहमति का पहला उत्तर पुलिस बल होना चाहिए, या संवाद का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए?

निस्संदेह, कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार का दायित्व है। यदि हिंसा होती है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है तो प्रशासन हस्तक्षेप करेगा ही। लेकिन लोकतंत्र की परिपक्वता का आकलन केवल इस बात से नहीं होता कि उसने कानून कैसे लागू किया; उससे भी अधिक इस बात से होता है कि उसने असंतोष को समय रहते सुना या नहीं। संवाद की विफलता अक्सर टकराव का पहला कारण बनती है।

इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसने नई पीढ़ी को लेकर बनी कई रूढ़ धारणाओं को तोड़ दिया है। लंबे समय से कहा जाता रहा कि आज का युवा केवल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और निजी करियर तक सीमित है। लेकिन जंतर-मंतर, पटना और देश के अनेक शहरों में दिखाई देने वाली भीड़ ने इस धारणा को चुनौती दी। हजारों छात्र-छात्राएँ अपनी पढ़ाई, नौकरी और निजी सुविधाएँ छोड़कर सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में युवतियों की सक्रिय भागीदारी ने इस आंदोलन को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया। अनेक युवतियों ने कहा कि आंदोलन के बीच उन्हें बराबरी, सम्मान और सुरक्षा का अनुभव हुआ। किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की नैतिक शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण शायद ही हो। यह मान लेना भी भूल होगी कि यह असंतोष अचानक पैदा हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि वर्षों से तैयार हो रही थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर उठते सवाल, भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार विलंब, बेरोज़गारी का दबाव, शिक्षा की बढ़ती लागत और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना—इन सबने मिलकर युवाओं के भीतर गहरा अविश्वास पैदा किया है। जब किसी समाज का परिश्रमी युवा अपनी प्रतिभा से अधिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे, तब यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं रहती; यह लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसे का संकट बन जाती है।

पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति का बड़ा हिस्सा धार्मिक, सांस्कृतिक और पहचान आधारित मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। इन विषयों का अपना महत्व है, लेकिन इसी दौरान शिक्षा, विश्वविद्यालयों, शोध, रोजगार और सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता जैसे प्रश्न धीरे-धीरे सार्वजनिक बहस के हाशिए पर चले गए। वर्तमान छात्र आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शायद यही है कि उसने राष्ट्रीय विमर्श को फिर उन प्रश्नों की ओर मोड़ दिया है, जिनका सीधा संबंध करोड़ों युवाओं के भविष्य से है।

इतिहास बताता है कि जब भी युवाओं ने अपने समय के बुनियादी प्रश्नों को लेकर आवाज़ उठाई है, तब राजनीति को अपनी भाषा बदलनी पड़ी है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष को निर्णायक गति दी। 1974 के छात्र आंदोलन ने लोकतंत्र और जवाबदेही की बहस को नई दिशा दी। मंडल आंदोलन ने सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्रीय प्रश्न बनाया।

योजना के...

बी0एल0यादव

मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र बेघरों को मिल रहा है आवास

समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब विकास की धारा उन लोगों तक भी पहुंचे जो लंबे समय तक मुख्यधारा से दूर रहे हैं। जिन परिवारों के पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं होता, उनके सामने केवल आवास का संकट नहीं होता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सम्मान जैसी अनेक चुनौतियां भी खड़ी होती हैं। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से उन वर्गों को प्राथमिकता दी है, जो वर्षों से आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आज प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संचालित यह योजना उन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करा रही है जो प्राकृतिक आपदाओं, गंभीर बीमारियों, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं अथवा विशेष परिस्थितियों के कारण सुरक्षित आवास से वंचित थे। इस योजना के अंतर्गत वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, पछइया/गढ़इया लोहार, बैगा, चेरो, नट, बोक्सा, बंजारा, बांसफोर, बसोड़, धरकार, सपेरा, जोगी जैसे वंचित समुदायों के साथ-साथ दिव्यांगजन, कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार, कालाजार एवं जेई/एईएस से प्रभावित परिवार, प्राकृतिक आपदा पीड़ित तथा पति के मृत्योपरांत निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के शुभारंभ से लेकर वर्ष 2025-26 तक कुल 4.72 लाख आवासों का आवंटन किया जा चुका है, जिनमें से 4.55 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 93.36 प्रतिशत आवास पूर्णता यह दर्शाती है कि योजना केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारी जा रही है। योजना के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब तक 1.35 लाख से अधिक दिव्यांगजन, 1.07 लाख से अधिक प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार, 74 हजार से अधिक निराश्रित विधवा महिलाएं, 50 हजार से अधिक मुसहर परिवार, 33 हजार से अधिक कोल समुदाय, करीब 10 हजार थारू परिवार सहित अनेक विशेष वर्गों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। यह आंकड़े सामाजिक न्याय के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 1.16 लाख नए आवासों का बजटीय प्रावधान किया है। इनमें से 52 हजार आवासों का पंजीकरण पहले ही किया जा चुका है तथा शेष प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही हाल ही में जारी शासनादेश के माध्यम से प्रदेश में निवासरत सभी जनजातियों को भी योजना की प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है, जिससे अधिक से अधिक पात्र परिवार लाभान्वित हो सकें।

योजना के अंतर्गत कई जनपदों में क्लस्टर आधारित आवास निर्माण किया जा रहा है। खीरी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बलरामपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर तथा सोनभद्र जैसे जनपदों में विकसित हो रहे आवासीय क्लस्टर ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं।

शब्द

हमारे द्वारा अभिव्यक्ति का साधन भाषा है और शब्दों का चयन भाषा को सुसंस्कारित बनाती है। हमारे जीवन में शब्द की एक सही चोट, जीवन की दिशा-दशा को बदल सकती है। सूरज की एक किरण, तिमिर के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकती है। महत्व क्षमता और शक्ति का है, केवल फैलाव या विस्तार का नहीं हैं । जहर की एक बूंद हजारों प्राणों का, क्षण मे हरण कर सकती है। शब्द और अर्थ का आपसी सम्बन्ध अत्यंत गहन हैं । शब्द केवल ध्वनि या अक्षरों का समूह नहीं हैं , बल्कि वह अर्थ की वह वेदिका हैं, जिसमें ज्ञान और अनुभति संचित होती हैं । शब्द एक प्रकार का शरीर हैं और अर्थ उसकी आत्मा होता हैं । कभी शब्द कटोरे के समान होता हैं, जिसमें अर्थ का दूध संचित रहता हैं , कभी म्यान की तरह , जिसमें तलवार रूपी अर्थ सुरक्षित रहता हैं। इसी प्रकार शब्द एक पेटी, मंजूषा या तिजोरी का रूप भी धारण करता हैं , जिसमें अर्थ का समान या आभूषण सुरक्षित रहता हैं । ज्ञान की प्राप्ति में शब्द का महत्व अत्यंत हैं । संसार के महान प्रवचनकार अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को प्रबद्ध करते हैं । शब्द की उपेक्षा करके ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करना अक्सर निरर्थक साबित हो सकता हैं । शब्द में भी सहलाने की या दर्द देने की , मलहम की और कुरेदने की , निर्माण की और बर्बादी की , सुलझाने की और उलझाने की , शांति की और फ़साद की आदि - आदि ताक़त होती हैं । ये सारा विवेक , समय ,क्षेत्र भाव और सीमा पर निर्भर है । बहुत पुरानी बात याद आती है कि works Hard , He works hardly. वे जबरदस्त नेता है , वे जबरदस्ती के नेता है। खाइये खाइये शर्माए नहीं , खाइये खाइये शर्म तो है नहीं। हमारे जीवन में भाषा विवेक पर बहुत ही महत्वपूर्ण परामर्श हैं । वह शब्दो के हेरफेर से केसर भी कैंसर बन जाता है और क्षीरसागर खारा सागर बन जाता हैं । इंसान विचारों को वश में रख शब्द बनाता हैं और शब्दों को वश में रख वो भाव प्रकट करता हैं । और शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से समझ आता है अन्यथा स्वागत तो पायदान पर भी लिखा होता है । इसलिए मन की पवित्रता पर मनुष्य का व्यक्तित्व निर्भर है।

> प्रदीप छाजेड़

जरा हटके

सोनभद्र में बेटियों के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला बनी 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'

उत्तर प्रदेश को महिला सशक्तिकरण, समानता और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' जनपद सोनभद्र में बालिकाओं के स्वर्णिम भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला साबित हो रही है। यह महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी योजना जिले के शहरी क्षेत्रों से लेकर सुदूर ग्रामीण और वनांचल इलाकों तक बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा तक निरंतर आर्थिक संबल प्रदान कर समाज में एक नई चेतना का संचार कर रही है। राज्य सरकार की इस युगांतकारी पहल का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कन्या भूरण हत्या जैसी अमानवीय कुरीतियों को समूल नष्ट करना, बाल विवाह की कुप्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर में ऐतिहासिक सुधार के साथ समान सामाजिक स्तर पर लाकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना है। जनपद सोनभद्र में इस कल्याणकारी नीति ने बेटियों के प्रति समाज के पारंपरिक और संकीर्ण दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे अब बेटियों का जन्म किसी परिवार पर आर्थिक भार नहीं, बल्कि गौरव और सौभाग्य का प्रतीक माना जा रहा है। जनपद सोनभद्र में जिला प्रशासन के संवेदनशील प्रयासों और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के फलस्वरूप इस योजना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप ले लिया बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता को छह सुव्यवस्थित चरणों में विभाजित किया

गया है। योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत जनपद में बालिका के जन्म होने पर (एक वर्ष के भीतर आवेदन करने की स्थिति में) 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे नवजात बेटी के शुरुआती लालन-पालन, पोषण और देखभाल में परिवारों को अत्यंत महत्वपूर्ण संबल मिल रहा है। इसके पश्चात द्वितीय चरण में बालिका के एक वर्ष की आयु तक के सभी अनिवार्य एवं जानलेवा बीमारियों से बचाव वाले टीकों के पूर्ण होने पर 2,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। जनपद सोनभद्र में इस चरण की सफलता से जहां एक ओर समयबद्ध संपूर्ण टीकाकरण को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला है, वहीं दूसरी ओर शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है, जो प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी दूरदर्शी सोच का जीवंत प्रमाण है। शिक्षा को बालिका सशक्तिकरण का सबसे सशक्त और स्थायी माध्यम मानते हुए प्रदेश सरकार ने इस योजना को विद्यालयी शिक्षा के हर स्तर से अत्यंत प्रभावी ढंग से जोड़ा है। जनपद सोनभद्र में बेटियों के प्रारंभिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में नामांकन को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने तथा ड्रॉप-आउट दर को शून्य पर लाने के लिए तृतीय और चतुर्थ चरण के तहत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तृतीय चरण में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये तथा चतुर्थ चरण के तहत छठी कक्षा में दाखिला लेने पर पुनः 3,000 रुपये की सहायता राशि अभिभावकों के खातों में भेजी जा रही है। इस वित्तीय व्यवस्था ने जिले के गरीब और सीमित संसाधनों वाले परिवारों को अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया है, जिससे प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं की भागीदारी में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। इसके आगे, किशोरावस्था में बेटियों की शिक्षा बाधित न हो और वे उच्च कक्षाओं की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा सकें, इसके लिए पंचम श्रेणी के अंतर्गत कक्षा नौ में प्रवेश लेने पर बालिका को 5,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद सोनभद्र के ग्रामीण अंचलों में यह आर्थिक संबल माध्यमिक स्तर पर बेटियों के पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने और उन्हें अपनी शैक्षणिक यात्रा जारी रखने में एक रक्षा कवच का कार्य कर रहा है। योजना के छठे एवं अंतिम चरण के तहत बालिका द्वारा 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक अथवा न्यूनतम दो वर्ष की अवधि वाले व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपये की एकमुश्त महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है। जनपद सोनभद्र में इस प्रावधान ने उन मेधावी एवं महत्वाकांक्षी बेटियों के सपनों को नए पंख दिए हैं, जो पहले उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस और अन्य खर्चों के डर से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को विवश हो जाती थीं। आज प्रदेश सरकार के इस संबल से जिले की बेटियां इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण कर रही हैं। आंकड़ों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि जनपद सोनभद्र में जन्म और टीकाकरण से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा तक, हर पड़ाव पर हजारों बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित होकर अपने सपनों को साकार कर रही हैं। प्रदेश सरकार सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को निभाते हुए योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के मध्यस्थ या बिचौलिए की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त कर चुकी है। जनपद सोनभद्र के समस्त पात्र लाभार्थियों को सभी प्रकार की वित्तीय सहायताओं का भुगतान सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली के माध्यम से उनके या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में किया जा रहा है।

900 सीटों की क्षमता ■ सहारा शहर में 200 एकड़ में तैयार होगा नया परिसर

कमल जैसी बनेगी नई विधानसभा

तैयारी

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । लखनऊ को जल्द नया विधानसभा भवन मिल सकता है। गोमती नगर के सहारा शहर में कमल की आकृति जैसा नया विधानसभा परिसर बनाने की तैयारी है। यह परिसर करीब 200 एकड़ में बनेगा। इसमें विधानसभा, विधान परिषद और संयुक्त सत्र के लिए अलग-अलग भवन होंगे। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अगले साल निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इसे आधुनिक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। भवन का वास्तुशिल्प कमल की आकृति जैसा होगा। यह भारतीय संस्कृति और उत्तर प्रदेश की पहचान

को दर्शाएगा। यह परियोजना केवल नया विधानसभा भवन नहीं होगी, बल्कि लखनऊ के लिए एक नया आर्किटेक्चरल लैंडमार्क भी बनेगी। आधुनिक डिजाइन, विशाल परिसर और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यह भवन उत्तर प्रदेश की नई प्रशासनिक सोच और भविष्य की आवश्यकताओं का प्रतीक होगा। उत्तर प्रदेश के नए विधान भवन के मॉडल को ऊपर से देखने पर मुख्य विधानसभा भवन कमल की पंखुड़ियों की तरह दिखाई देगा। इस परिसर में केवल विधानसभा ही नहीं, बल्कि आधुनिक सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, विधायक हॉस्टल, और वीवीआईपी प्रशासनिक ब्लॉक भी शामिल होंगे। इस नए सदन में 700 विधायकों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही प्रत्येक जिले के प्रतिनिधियों के लिए अलग-अलग चर्चा की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण कंसलटेंट और आर्किटेक्ट के माध्यम से इसका नक्शा और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा रहा है।

डिजिटल सुविधाओं से लैस होगा नया भवन

नई इमारत में 700 सदस्यों की क्षमता वाला विधानसभा सदन और 200 सदस्यों की क्षमता वाला विधान परिषद सदन बनाया जाएगा। दोनों सदनों में आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था होगी।

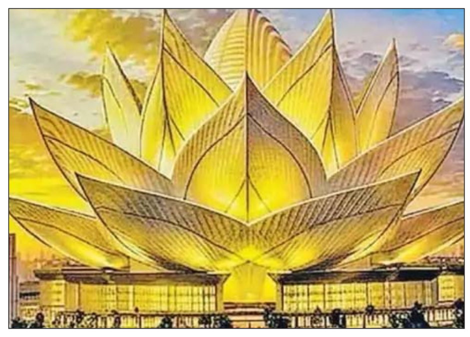

■ नए विधानसभा भवन का प्रस्तावित मॉडल कमल के फूल की आकृति पर आधारित है। (सांकेतिक तस्वीर)

संयुक्त सत्र के लिए 1000 सीटों का हॉल

नए विधानसभा परिसर में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र के लिए 1000 सीटों का बड़ा हॉल बनाया जाएगा। यहां बड़े सरकारी कार्यक्रम और विशेष आयोजन भी हो सकेंगे।

> प्रस्ताव के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य अगले वर्ष शुरू होने की उम्मीद है। इसे उत्तर प्रदेश में आधुनिक प्रशासनिक ढांचे और राजधानी लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई पहचान देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल माना जा रहा

5 हजार से ज्यादा वाहनों की पार्किंग

परिसर में 5,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा चौड़ी सड़कें, हरित क्षेत्र, प्रशासनिक कार्यालय और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

हजरतगंज दो युवकों ने किया आत्मदाह का प्रयास

जमीन कब्जे की शिकायत पर सुनवाई न होने से थे परेशान

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ के हजरतगंज में शुक्रवार को दो युवकों ने आत्मदाह की कोशिश की। दोनों डीजल से भरी बोतल लेकर पहुंचे थे और खुद पर डीजल डालने लगे। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुबग्गा निवासी चाचा-भतीजे ने आत्मदाह की कोशिश की। इनका आरोप है कि उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कई स्तरों पर शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसी से आहत होकर दोनों ने हजरतगंज पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और युवकों द्वारा लगाए

गए आरोपों की भी पड़ताल की जाएगी। घटना के दौरान कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से स्थिति जल्द ही सामान्य कर ली गई। लखनऊ के मलिहाबाद तहसील स्थित दुबग्गा थाना क्षेत्र के लीलाखेड़ा कटौली के रहने वाले राम गणेश और उनके भतीजे सतीश कुमार गौतम ने आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें समय रहते बचा लिया और हजरतगंज थाने ले आए। पूछताछ पीड़ित राम गणेश ने बताया कि गांव में उनकी एक पुश्तैनी जमीन पर उनके परिवार के ही सुनील नाम के व्यक्ति ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है।

फास्ट न्यूज

इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 25 जुलाई से बदलेगा ट्रैफिक

लखनऊ । लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर लंबे समय से लगने वाली जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य 25 जुलाई से शुरू होगा। निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस ने अगले आदेश तक अस्थायी डायवर्जन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। जरूरत के अनुसार डायवर्जन व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

लखनऊ में 4 फर्मों और 4 कारोबारियों पर एफआईआर

लखनऊ । राजधानी लखनऊ में नकली दवाओं के कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की जांच के बाद अमीनाबाद थाने में चार फर्मों और उनके चार संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

आरोप है कि इन लोगों ने नकली और काउंटरफिट थ्रोंबोफोब ऑइंटमेंट 20gm की खरीद-बिक्री कर बाजार में बेचा और भारी मुनाफा कमाया। जांच में यह भी सामने आया कि 24 हजार ट्यूब दवा का न तो भौतिक स्टॉक मिला और न ही उसके खरीद संबंधी मूल बिल उपलब्ध कराए गए।

20 साल के युवक ने दी जान

मोहनलालगंज । लखनऊ के मोहनलालगंज में शुक्रवार सुबह एक 20 साल के युवक ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में शोक छा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान उतरगांव निवासी कमलेश लोधी (20) पुत्र स्व. नरेंद्र कुमार के रूप में हुई है।

संजय कुमार पाण्डेय ग्राम्य विकास उ०प्र० को किया गया निलम्बित

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा श्री संजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ०प्र० को, जनपद उन्नाव में उपायुक्त, (स्वतः रोजगार), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर तैनाती की अवधि में की गयी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रथमदृष्ट्या दोषी होने व उनके द्वारा लोकपालों का कार्यकाल दिनांक 15.03.2026 को पूर्ण होने के पश्चात् उनका कार्यकाल विस्तार/नवीनीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव/पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने, तथा संबंधित विशेषज्ञ के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करने, भारत सरकार के निर्देशों एवं शासनादेश का उल्लंघन करने, मनरेगा के विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कोई उचित पर्यवेक्षण/कार्यवाही नहीं करने आदि के कारण तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है।निलम्बन की अवधि में श्री संजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ०प्र०, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

संजय कुमार पाण्डेय के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली- 1999 के नियम -7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त (मनरेगा) ग्राम्य विकास विभाग के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

टाटा मोटर्स के जॉब फेयर में उमड़ी भीड़

लखनऊ। लखनऊ के देवा रोड स्थित टाटा मोटर्स प्लांट में शुक्रवार को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) के तहत जॉब फेयर आयोजित किया गया। कंपनी ने 500 अभ्यर्थियों को बुलाया था, लेकिन करीब 2,500 युवक-युवतियां पहुंच गए। भीड़ अधिक होने के कारण पहले दिन करीब 2,000 अभ्यर्थियों की ही स्क्रीनिंग हो सकी। बाकी अभ्यर्थियों को अगले दिन आने के लिए कहा गया।

जॉब फेयर में बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा समेत कई जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें पहुंचने का समय तो बताया गया था, लेकिन प्रक्रिया कितनी देर चलेगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं, प्लेसमेंट सेल के अधिकारियों ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा अभ्यर्थी आने की वजह से सभी की स्क्रीनिंग एक दिन में पूरी नहीं हो सकी। इसलिए बाकी अभ्यर्थियों को अगले दिन बुलाया गया है।

लखनऊ में युवाओं की 600मीटर लंबी कतार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे

लिपस्टिक-नेल पॉलिश से नारे लिखे, ढपली बजाई

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । लखनऊ में कई संगठनों के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के समर्थन में जुटे हैं। इनमें AISA, SFI, NSUI और समाजवादी छात्र सभा समेत LGBTQ के लोग भी शामिल हैं।

छात्रों ने ढपली बजाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। वहीं, LGBTQ के युवक-युवतियों ने लिपस्टिक और नेल पॉलिश से पोस्टरों पर नारे लिखे। पहले सभी परिवर्तन चौक पर इकट्ठा हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए करीब 2 किमी दूर शहीद स्मारक की तरफ बढ़ रहे हैं। यह भीड़ सड़क पर करीब 600

प्रदर्शन में शामिल प्रिंस प्रकाश ने कहा- यह आम छात्रों और हिंदुस्तान के युवाओं का प्रोटेस्ट है। 2027 में जनता यूपी में जवाब देगी।

मीटर लंबी कतार में है।

प्रदर्शन में शामिल हुए प्रदीप शर्मा ने कहा- देश में अब तक 158 पेपर लीक हुए हैं। NEET के पेपर लीक के सभी जिम्मेदारों को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग छात्रों को सपोर्ट देने के लिए आज परिवर्तन स्थल से शहीद स्मारक तक मार्च निकालेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कबीर ने कहा- यह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं, देश की शिक्षा का मसला है। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया गया है।

■ परिवर्तन चौक पर करीब 4:20 बजे युवा, महिलाओं और बुजुर्ग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए।

धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो लिखा हुआ बैनर लेकर चल रहे प्रदर्शनकारी

मार्च में सबसे आगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो लिखा हुआ बैनर लेकर युवा चल रहे हैं। इनके पीछे जबरदस्त भीड़ है। लखनऊ के एडवा संगठन की हेड मधु गर्ग ने कहा- आज देश के हर शहर में उबाल आ गया है। यह जनता का मुद्दा है। जनता के मुद्दे पर ही राजनीति होती है।

लखनऊ और यूपी के सभी 75 जिलों में कैंडिल मार्च

नीट - लाठीचार्ज विवाद पर प्रदेशव्यापी आंदोलन

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। नीट, सीबीएसई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं तथा दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में यूपी कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी जहां आज शाम को लखनऊ में कैंडिल मार्च निकालेगी। वहीं, शनिवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ कैंडिल मार्च और सत्याग्रह आयोजित करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे लेकर सभी जिला और शहर कांग्रेस कमेटियों को निर्देश जारी किए हैं।

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई बर्बरतापूर्ण था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों

पर जिस तरह बल प्रयोग किया गया, वह लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। यह आंदोलन केवल लाठीचार्ज के विरोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शनिवार को प्रदेश के सभी जनपदों में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटियों के नेतृत्व में कैंडिल मार्च निकाला जाएगा। मार्च का समापन संबंधित जिलों में महात्मा गांधी या डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर होगा, जहां सत्याग्रह भी किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉ. सी.पी. राय ने कहा कि पार्टी परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है।

> “ प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार आज शाम छह बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से गांधी प्रतिमा, जीपीओ तक कैंडिल मार्च निकाला जाएगा। इसमें पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र और युवा बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

अजय राय बोले- छात्रों पर लाठीचार्ज अस्वीकार्य

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़ी है और पूरे प्रदेश में विरोध दर्ज कराएगी।

दुकानों के शटर काटकर चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया

लखनऊ। लखनऊ में बंद दुकानों को निशाना बनाकर शटर काटने वाले शातिर चोरों के गैंग का मड़ियांव पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने शुक्रवार को गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें, जनरेटर के पार्ट्स, दुकान से चोरी किया गया सामान, 44 हजार रुपए नकद, चोरी में इस्तेमाल डाला, कटर और लोहे की रॉड बरामद की है। गिरोह शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दुकानों, जनरेटर और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देता था।

पुलिस के मुताबिक, 5 जुलाई को त्रिवेणीनगर निवासी शुभम चौरसिया की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की गई थी। इस मामले में मड़ियांव थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कोयला ढलान के पास घेराबंदी कर चार संदिग्धों को चोरी के सामान से लदे डाले के साथ पकड़ लिया।

मंत्री आवास घेरने पहुंचे अभ्यर्थियों को ले गई पुलिस

युवक बेहोश, महिला के बच्चे को पुलिस ने गोद में लिया

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में शुक्रवार सुबह 69 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11:10 बजे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंच गए और घेराव शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी अचानक बेहोश होकर गिर गया। जबकि अपने छोटे बच्चे के साथ पहुंची एक महिला अभ्यर्थी का बच्चा पुलिसकर्मियों ने गोद में लेकर संभाला। प्रदर्शन के दौरान करीब 60 अभ्यर्थियों ने योगी बाबा न्याय करो के नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की शुरू हो गई। करीब 30 मिनट तक हंगामा चला। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हाथ-पैर पकड़कर उठाया, बसों में बैठाया और हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। करीब 60 अभ्यर्थी प्रदेश

के अलग-अलग जिलों से लखनऊ पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ धोखा किया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में 8,270 सीटों को लेकर एफिडेविट दाखिल किया है। इसमें 4,946 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं, जो पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया से तीन बार बाहर हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग 6,800 सीटों पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की थी, लेकिन सरकार की नई प्रक्रिया के चलते अब केवल करीब 3,300 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति मिल पाएगी।

योजना : बुंदेलखंड के विकास को नई गति, पेयजल के साथ रोजगार और ऊर्जा क्षेत्र को भी मिलेगा नया विस्तार

बेटे-बेटियों की अच्छी शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी : ए.के. शर्मा

- 83.24 करोड़ की गुरसराय-गरौठा पेयजल योजना का लोकार्पण, हजारों परिवारों को मिलेगा शुद्ध पेयजल : ए.के. शर्मा
- मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड में तेज़ी से साकार हो रही विकास परियोजनाएं
- डिफेंस कॉरिडोर, सौर ऊर्जा और पेयजल परियोजनाएं बदलेंगी बुंदेलखंड की तस्वीर

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने झांसी जनपद में 83.24 करोड़ की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद एवं गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से गुरसराय और गरौठा के लगभग 7740 घरों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अपने संबोधन में मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री

बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे

मंत्री शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इनके पूर्ण होने के बाद लोगों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र ऊर्जा के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा।उन्होंने बुंदेलखंड में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि इन परियोजनाओं का सर्वाधिक लाभ स्थानीय युवाओं को मिले। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को उनके अपने क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, जिससे पलायन रुके और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

उन्होंने कहा कि यह पेयजल परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के स्वास्थ्य, सम्मान और बेहतर जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है।

एलआईसी बीमा सखी कार्यक्रम से आत्मनिर्भर बन रहीं ग्रामीण महिलाएँ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान

- बीमा सखियों ने छह माह में अर्जित किया रु 02 करोड़ से अधिक का सामूहिक कमीशन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भरता को नई गति प्रदान कर रही है। इसी दिशा में एलआईसी का बीमा सखी कार्यक्रम महिलाओं के लिए सम्मानजनक आजीविका, स्वरोजगार और वित्तीय नेतृत्व का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बीमा सखी के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे वे अपने परिवार की

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के साथ-साथ ग्रामीण समाज में वित्तीय जागरूकता का भी विस्तार कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें विकास यात्रा का सक्रिय सहभागी और नेतृत्वकर्ता बनाना है। एलआईसी बीमा सखी कार्यक्रम इसी सोच का सशक्त उदाहरण है, जिसने हजारों ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक आजीविका के नए द्वार खोले हैं। उन्होंने कहा कि बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण परिवारों तक बीमा सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा का संदेश भी प्रभावी ढंग से पहुँच रहा है। आज बीमा सखियाँ अपने कार्य से न केवल परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार बन रही हैं, बल्कि अपने गाँवों में वित्तीय जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक के रूप में भी नई पहचान स्थापित कर रही हैं। मौर्य ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार की महिला-केंद्रित योजनाओं तथा स्वयं सहायता समूहों की सशक्त भागीदारी से उत्तर प्रदेश में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक गति पकड़ेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।

शंकराचार्य बोले-आंदोलन के लिए कैसी अनुमति, सरकार हमारे खाने-रुकने का इंतजाम करे

योगी के पास एक लाख गाय लेकर पहुंचेंगे : शंकराचार्य

सभा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने शुक्रवार को लखनऊ में 'गो-संरक्षण आंदोलन' के अगले चरण का ऐलान किया। उन्होंने गौ गर्जना अक्षौहिणी संकल्प सभा में कहा कि देश के गांव-गांव तक गोमाता के लिए आंदोलन चलेगा। यूपी के एक लाख सात हजार गांवों से गोमाता लखनऊ लाएंगे। उन्हें सीएम योगी से मिलाएंगे।

इस बार आंदोलन के लिए सरकार से अनुमति नहीं मांगेंगे। 17 अगस्त से आंदोलन शुरू होगा। 17 नवंबर को बड़ी संख्या में लोग लखनऊ में जुटेंगे। यहां 11 दिन रहेंगे। उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- हमारे आंदोलन के लिए सरकार को मैदान और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। दरअसल, बीते 11 मार्च को लखनऊ में आयोजित 'शंखनाद सभा' के दौरान 24 जुलाई को बड़े कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। आयोजन समिति का कहना है कि औपचारिकताएं 3 जुलाई को पूरी कर ली गई थीं। जब 36 घंटे पहले तक अनुमति नहीं मिली तो समर्थकों से गौ गर्जना अक्षौहिणी संकल्प सभा को विधानसक्षा क्षेत्र स्तर पर करने के लिए कहा गया।

दिल्ली और गांवों की ओर बढ़ेगा आंदोलन

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि लखनऊ कार्यक्रम के बाद 11 दिन तक इंतजार किया जाएगा। इसके बाद आंदोलन का अगला चरण शुरू होगा। इसमें एक टोली दिल्ली की ओर जाएगी, जबकि दूसरी टोली उत्तर प्रदेश के गांवों में जाकर गो-संरक्षण के लिए जनजागरण अभियान चलाएगी।

छत्तीसगढ़ में सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर लगेगा

अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि 14 से 17 अगस्त (श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया से पंचमी) तक छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधियों का सम्मेलन और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही 17 अगस्त से प्रदेश और देशभर में 'एक नोट अभियान' शुरू किया जाएगा। इसके तहत हर व्यक्ति से आंदोलन के लिए एक नोट का सहयोग देने की अपील की जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 'गो माता के नाम कांवड़ यात्रा' निकालने का अभियान भी शुरू किया जाएगा, ताकि गो-संरक्षण के प्रति लोगों को जोड़ा जा सके।

काशी में होगा 11 दिन का गौ प्रतिष्ठा यज्ञ

शंकराचार्य ने कहा कि शारदीय नवरात्र के दौरान काशी में 11 दिवसीय गौ प्रतिष्ठा यज्ञ आयोजित होगा। इसमें लाखों लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि यज्ञ के दौरान गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प दिलाया जाएगा और लोगों से गौ संरक्षण के पक्ष में खड़े होने का आह्वान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया से उत्तर प्रदेश के हर गांव से एक-एक नंदी या आनंदी (प्रतीकात्मक यात्रा) निकलेगी। यह यात्रा विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अष्टमी (गोपाष्टमी के दिन लखनऊ पहुंचेगी। शंकराचार्य का दावा है कि प्रदेश के 1.07 लाख गांवों से यह अभियान चलाया जाएगा।

काशी में रेलवे अफसर को सीबीआई पकड़कर ले गई

कारोबारी से 1.70 लाख रुपए रिश्वत ली, मोबाइल-लैपटॉप जब्त

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी। यूपी के वाराणसी में CBI ने रेलवे के एक सीनियर अफसर को छापेमारी कर पकड़ा है। उन पर फर्नीचर कारोबारी से बिल पास करने के लिए 1.70 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है।

कारोबारी की शिकायत पर गुरुवार शाम CBI ने DRM ऑफिस और अफसर के आवास पर एक साथ छापेमारी की। टीम ने परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की।

CBI ने आरोपी अफसर नितेश अग्रवाल को हिरासत में ले लिया। उनका मोबाइल, लैपटॉप और कुछ फाइलों को भी कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि उनके घर से कुछ रुपयों की बरामदगी भी हुई है।

नितेश अग्रवाल

नितेश बनारस रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक (सीनियर DMM) हैं। वह यहां 3 साल से तैनात थे।

नीतेश अग्रवाल के पास पूरे मंडल के रेलवे कर्मचारियों को ड्रेस-जूते आदि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा, आवश्यक उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स और अन्य जरूरी सामान की स्थानीय स्तर पर खरीद जैसी जिम्मेदारी थी। सूत्र बताते हैं कि करीब 2 महीने पहले रेलवे यूनियन ने भी पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के डीआरएम से शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि रेलवे कर्मियों के लिए जो ड्रेस और जूते खरीदे जा रहे हैं। उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। उनमें डिफेक्ट है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, उससे अफसरों का कमीशन सेट है। इसके बाद रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम ने शिकायतों के आधार पर आरोपों की जांच की थी। फिर जांच रिपोर्ट सीबीआई को भेज दी। इस रिपोर्ट से मिले इनपुट के बाद लखनऊ सीबीआई टीम ने गुरुवार को नितेश के घर और आवास पर छापा मारा था।

डिप्टी डायरेक्टर को 10 हजार की घूस लेते पकड़ा

विजिलेंस टीम मुरादाबाद से पकड़कर बरेली ले गई

तमसा संकेत, एजेंसी

मुरादाबाद । मुरादाबाद में बरेली विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के डिप्टी डारेक्टर को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बीज सत्यापन और टैग जारी करने के नाम पर किसान से 70 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। बरेली उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान एसपी ने बताया- उपनिदेशक रूप सिंह ने बीज सत्यापन और टैग जारी करने के एवज में एक किसान से 70 हजार रुपए की मांग की थी। किसान ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो आरोपी ने 10 हजार रुपए तत्काल और बाकी राशि अगस्त के दूसरे सप्ताह में देने की बात तय कर ली। इसके बाद किसान ने पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान बरेली सेक्टर से मामले की लिखित शिकायत की। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर विजिलेंस टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। शुक्रवार को विजिलेंस टीम ने मुरादाबाद में शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए की नकद रिश्वत लेते समय उपनिदेशक रूप सिंह को रंगे हाथ पकड़ लिया।

उपनिदेशक रूप सिंह ने बीज सत्यापन और टैग जारी करने के एवज में एक किसान से 70 हजार रुपए की मांग की थी।

सपा विधायक की दौड़ पर भाजपा एमएलए ने चुटकी ली

कानपुर। कानपुर में सपा विधायक के सत्याग्रह के दौरान घर में हुए हाउस अरेस्ट के बीच बैरिकेडिंग हटाकर दौड़ लगाकर भागे अमिताभ बाजपेई पर बीजेपी विधायक सुरेन्द्र मैथानी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा, हो सकता है विधायक जी इसलिए भागे होंगे कि सोचा होगा दौड़कर बीजेपी में शामिल हो जाऊं, लेकिन यहां कोई गुंजाइश नहीं है।

दूसरा ये कि उनके सत्याग्रह के बैनर में कहीं सपा का नाम और निशान नहीं है। सपा से दूरी इसकी पुष्टि कर रही है। शायद वो बीजेपी में आना चाहते हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। इस पर विधायक अमिताभ बाजपेई ने भी कहा कि उन्होंने छात्रों की लड़ाई के लिए छात्रसंघ के पूर्व पदाधिकारियों को एकत्र कर यह सत्याग्रह किया। स्वयं भी कानपुर के पीपीएन कॉलेज से महामंत्री रहे हैं। दौड़ लगाकर भागने पर वो बोले, "मैं तो पुलिस की फिटनेस चेक कर रहा था।"

भाई को बचाने में बहन भी डूबी दोनों की मौत उम्र 3, 5 साल

गाजीपुर में लाश देख मां बोली- हे भगवान, मेरे बच्चों को लौटा दो

तमसा संकेत, एजेंसी

गाजीपुर । गाजीपुर में शुक्रवार दोपहर गंगा नदी में डूबने से भाई-बहन की मौत हो गई। 3 साल के बच्चे का नदी किनारे पैर फिसल गया था, जिससे वह पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए उसकी 5 साल की बहन भी नदी में कूद गई। कुछ ही देर में दोनों डूब गए।

नदी के दूसरी ओर बैठे एक युवक ने दोनों को डूबते देखा और शोर मचाया। आवाज सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे। दोनों को बाहर निकालकर पहले सीपीआर दिया। फिर एंबुलेंस से सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मां रो-रोकर कहने लगीं - भगवान, मेरे बच्चों को लौटा दो।

प्रिया, बहन

कृष्णा, भाई

करंडा थाना क्षेत्र के माहेपुर गांव के रहने वाले किसान संतोष बिंद के परिवार में पत्नी हेमवंती, बेटा कृष्णा (3), बेटी प्रिया (5) और बुजुर्ग माता-पिता थे।

संतोष ने बताया- मेरे पिता रामअवध बिन्द खेत पर गए थे। उनको खोजते हुए दोनों बच्चे सुबह करीब साढ़े 8 बजे घर से 300 मीटर दूर खेत की तरफ निकल गए। तभी दोनों गंगा नदी के किनारे पहुंच गए और खेलने लगे। करीब आधे घंटे तक दोनों खेलते रहे।

हाथ-पैर रगड़कर सीपीआर दी, लेकिन जान नहीं बची

गांव के संतोष ने बताया कि बच्चों को नदी से निकालने के बाद उनके तलवे रगड़े गए। पेट और छाती दबाकर पानी निकालने की कोशिश की गई। सीपीआर भी दी गई, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। इसके बाद दोनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर

पत्रांक 486/न०पा०प०टा०/2026-27 दिनांकः- 23.07.2026

अति अल्पकालीन पुनः ई-निविदा (Retender) सूचना

नगर पालिका परिषद, टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर के द्वारा स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में A/B/C/D/E श्रेणी (जैसा लागू हो) में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर राज्य वित्त आयोग मद के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या 213/न०पा०प०टा०/2026-27 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा 04 निर्माण कार्य की ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसमें पर्याप्त बिड प्राप्त न होने के कारण पुनः ई-निविदा (Retender) आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिए निविदा दे सकता है।

1- कार्य का विवरण वेबसाइट https://www.tender.up.nic.in पर लॉगइन कर देखा जा सकता है।

2- वेबसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता की तिथि दिनांक 24.07.2026 से दिनांक 03.08.2026 तक।

3- प्री-बिड मीटिंग की तिथि व समय दिनांक 29.07.2026 समय 12:00 बजे।

4- ई-निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि / समय दिनांक 03.08.2026 समय 12:00 बजे।

5- ई-निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि / समय दिनांक 03.08.2026 समय अपरान्ह 02:00 बजे।

6- निविदा आमंत्रणकर्ता को आई०टी०बी० के क्लाज-9 के अनुसार परिशिष्ट / शुद्धिपत्र जारी करने का अधिकार है, जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी सम्भावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल की निगरानी रखें।

7- अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट https://www.tender.up.nic.in पर लॉगइन करें तथा बिड को डाउनलोड करें।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
टाण्डा अम्बेडकरनगर

पृष्ठ 01 का शेष...

नेशनल टेस्टिंग ...

जबकि विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय सचिव बना दिया गया है।

PM ने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक रोकने के लिए पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो। इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया।

वहीं यह भी एलान किया था कि पेपर लीक रोकने के लिए अगले हफ्ते संसद में नया बिल पेश किया जाएगा। इसे जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने इससे पहले एलान किया था कि पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।

पेपर लीक से जुड़े मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे मामले का निपटारा करें और तीन महीने के भीतर सजा सुनाएं।

NEET UG पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली में सुधार और मई में NEET-UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की जा रही है।

पेपर लीक की मांगों के खिलाफ एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन का अनशन किया था और संसद में भी हंगामा जारी है। इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। अब तक अलग-अलग राज्यों से 13 आरोपी पकड़े जा चुके हैं।

पेपरलीक संशोधन ...

हालांकि, उन्होंने मजाक में एक रिपोर्टर से कहा- आज कोई पेपर लीक नहीं हो रहा।

दरअसल, पीएम मोदी ने गुरुवार रात एक वीडियो जारी करके कहा था कि पेपर लीक संशोधन बिल पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी, फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा।

धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल ...

इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 100 से ज्यादा छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साहिल इनमें से एक है। राहुल ने जिस छात्र की चोट दिखाई। उसका नाम साहिल लोचाब है। वह 19 साल का है और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की पैलेट गन से इनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। AIIMS के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में सर्जरी हुई है। परिवार के मुताबिक, डॉक्टरों ने बताया है कि घायल आंख की रोशनी लौटने की सिर्फ 1% संभावना है, क्योंकि आंख की पुतली को गंभीर नुकसान पहुंचा है। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के छात्र हैं। उनकी मां ज्योति ने बताया, 'वह पहले भी CJP के प्रदर्शन में गया था। सोमवार को भी यह कहकर गया कि यह उसके लिए जरूरी है और उसकी पढ़ाई से जुड़ा मुद्दा है। वह हमेशा पुलिस अधिकारी बनना चाहता था।' केंद्र ने संसद में बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आय 2019-20 में 504 करोड़ थी,जो 2023-24 में बढ़कर 1,116 करोड़ हो गई। इसी दौरान खर्च 440 करोड़ से बढ़कर 1,040 करोड़ पहुंच गया। सरकार ने बताया कि 2018 में बनने के बाद NTA ने 270 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित कीं, जिनमें 6.6 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। 2026 में अब तक 12 परीक्षाएं कराई गई हैं, जिनमें 65 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। NTA में 39 स्थायी पद हैं। इसके अलावा 73 संविदा और 124 आउटसोर्स कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन के तहत 'वंदे मातरम्' के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है।

सोनम वांगचुक की ...

वांगचुक ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। उनके लिए सबसे अहम बात छात्रों पर कार्रवाई रुकवानी थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना जरूरी नहीं था। वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुशी जताई। हालांकि, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा।

विभिन्न दलों के करीब 65 सांसद उनसे मिले या उन्होंने संदेश भेजकर भरोसा दिलाया कि वे संसद में NEET पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली का मुद्दा उठाएंगे।

दो दिन तक चली बातचीत के बाद बनी सहमतिः सरकार के साथ लिखित आश्वासन को लेकर लगातार दो दिन बातचीत हुई। इसी वजह से उन्होंने अनशन दो दिन और जारी रखा और आखिरकार सहमति बनने पर इसे समाप्त किया।

अब सोशल-मीडिया ...

इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के अलावा मेटा और एक्स (X) को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है।

याचिका में कोर्ट की कार्यवाही के मॉनिटाइजेशन पर चिंता जताई गई है। कहा गया है कि सुनवाई के चुनिंदा हिस्सों को शरारतपूर्ण तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। यह जजों और वकीलों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा है। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए समाज में भ्रम फैलाने में लगे हैं।

वहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने खुद हाल में अनुभव किया है कि उनके कुछ कथनों को गलत तरीके से प्रकाशित किया गया। उन्होंने एक हालिया मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सुबह 10 बजे तक कोई याचिका दाखिल नहीं हुई थी, लेकिन मीडिया में यह खबर चली कि उन्होंने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया।

जब पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करने की बात कही तो विकास सिंह ने अंतरिम आदेश की मांग की। इस पर पीठ ने कहा कि ₹बोतल से बाहर निकल चुके जिन्न को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता₹, लेकिन न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी है।

प्रधान के इस्तीफे पर ...

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया, 'दो घंटे की बातचीत में CJP ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमनें ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है।'

सरकार ने CJP के प्रवक्ताओं को कल फिर से 3:30 बजे मिलने बुलाया है। अगर अगले 2-3 दिन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो, CJP फिर से 20 जुलाई जैसा मार्च कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पेपर लीक के बाद से अभी तक हुए सुधारों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने केंद्र से अब तक मामले में हुई जांच के बारे में बताने के लिए भी कहा।

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट...

इस बीच, रैपिड एक्शन फोर्स ने भी जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पेलेट गन चलाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर RAF जवानों की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इनमें कुछ वीडियो में जवानों को बंदूक और लाठी का इस्तेमाल करते तथा लाठीचार्ज करते हुए देखा जा सकता है। वहीं कुछ वीडियो में प्रदर्शनकारियों द्वारा RAF जवानों को घेरकर उन पर हमला करते हुए भी दिखाया गया है।

सीएम के पैर छुए, सम्राट बोले- अगले आईपीएल ऑक्शन में बिहार की टीम भी रहेगी, 19 खिलाड़ियों को जॉइनिंग लेटर

क्रिकेटर आकाशदीप, मुकेश कुमार बने डीएसपी

नियुक्ति

पटना, एजेंसी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मेडल जीतने वाले 19 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का जॉइनिंग लेटर दिया।

इनमें भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और एथलेटिक्स खिलाड़ी पीयूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक (ASI) पद पर नियुक्ति दी गई।

वहीं आकाशदीप और मुकेश कुमार ने पैर छूकर मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया।

ऊर्जा ऑडिटोरियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया।

इस साल 106 खिलाड़ियों को लेटर पहले ही दिए जा चुका है। इस योजना में नियुक्ति-पत्र, खेल छात्रवृत्ति चयन-पत्र और खेल सम्मान राशि दी गई। सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि 15 सितंबर के बाद बिहार के सभी पंचायत में स्पोर्ट्स को लेकर टैलेंट की खोज की जाएगी।यह अभियान 6 महीने तक चलेगा। पूरे प्रदेश में जो भी खिलाड़ी मिलेगा, उसे प्रशिक्षित करके देश के लिए तैयार करने का काम किया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा- आने वाले IPL ऑक्शन में बिहार की टीम भी रहेगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण ने बताया, राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में सीधी नियुक्ति देकर खेल छात्रवृत्ति उपलब्ध कराकर उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है।

सेतु मिश्रा को 37.50 लाख रुपये की सम्मान राशि दी गई

एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में स्वर्ण और रजत पदक जीतने और एथलेटिक्स में अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी बने सेतु मिश्रा को 37.50 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई।

19 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति-पत्र मिला है

इसके अलावा समारोह के दौरान 5 पैरा खिलाड़ियों सहित विभिन्न खेल विधाओं के बाकी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी नियुक्ति-पत्र सौंपे गए।

मुख्यमंत्री ने सेतु मिश्रा को सौंपा 37 .50 लाख रुपये का चेक।

इसी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभास्कर कुमार को 2 लाख रुपये की सम्मान राशि दी गई। कॉमनवेल्थ यूथ शतरंज चैंपियनशिप-2026 की ब्लिट्ज स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली मरियम फातिमा को 9 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना-2026

- खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, पोषण, खेल सामग्री, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और खेल विज्ञान संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती
- हर साल 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 20 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है
- अभी के वित्तीय वर्ष में 637 खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति चयन-पत्र प्रदान किए जाएंगे
- उत्कर्ष योजना के 21, सक्षम योजना के 184, प्रेरणा योजना के 432 खिलाड़ी शामिल हैं
- प्रेरणा योजना में चयनित 432 खिलाड़ियों में से 269 खिलाड़ियों का चयन राज्यव्यापी 'मशाल प्रतिभा खोज कार्यक्रम' के जरिए हुआ है

मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने तिरंगा लेकर भारतीय दल की अगुआई की

कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी किंग चार्ल्स ने किया उद्घाटन

ग्लासगो, एजेंसी

कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई। ओवो हाइड्रो एरिना में दो बार की ओलिंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और टोक्यो ओलिंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने तिरंगा लेकर 125 सदस्यीय भारतीय दल की अगुआई की।

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने खेलों का उद्घाटन किया। इसके बाद भारत समेत 74 देशों के खिलाड़ियों ने मार्च-पास्ट में हिस्सा लिया।

भारत के लिए खेलों की शुरुआत भी शानदार रही। उद्घाटन समारोह से पहले ही भारतीय खिलाड़ियों ने लॉन बॉल्स में दो जीत दर्ज कर विजयी आगाज किया। पुतुल सोनोवाल ने वर्ल्ड चैम्पियन कनाडा के रेयान बेस्टर को मात दे दी।

महिला डबल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी ने भी अपना पहला मैच जीता। भारतीय जोड़ी ने 'ग्रुप बी' के मैच में माल्टा की रिक्कसन बहनों (रेबेका लुईस और कोनी-लेघ) को टाईब्रेकर में हराया।

वहीं भारतीय ध्वजवाहक लवलीना बोरगोहेन महिला 75 किलोग्राम वर्ग में सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण बिना मुकाबला खेले ही कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर चुकी हैं। ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत स्कॉटलैंड की संस्कृति, इतिहास और विरासत के विशेष वीडियो से हुई। इसके बाद किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला एरिना पहुंचे। उनके साथ प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम भी मौजूद रहे। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रगान 'गॉड सेव अवर किंग' प्रस्तुत किया गया और फिर एक-एक कर सभी 74 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने मार्च-पास्ट किया। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले इन खेलों में भारत 125 खिलाड़ियों का दल भेजा है। ओपनिंग सेरेमनी ग्लासगो के ओवो हाइड्रो एरिना में हुई, जहां करीब 13 हजार दर्शक मौजूद रहे। भारतीय दल इस बार एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग, लॉन बॉल्स समेत 10 खेलों में चुनौती पेश करेगा।

ऑस्ट्रेलिया सीईओ बोले-भारत बड़ा मार्केट, संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले शेड्यूल व्यस्त होना बड़ी चुनौती

ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड टेस्ट मैच भारत में कराने पर विचार

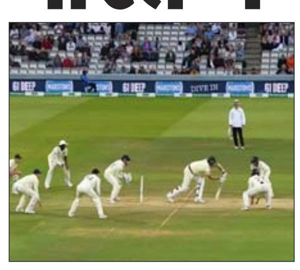

नई दिल्ली, एजेंसी

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि भविष्य में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भारत में टेस्ट मैच कराने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में क्रिकेट के लिए बड़े मौके हैं, हालांकि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस साल दिसंबर में पहली बार बिग बैश लीग (BBL) का ओपनिंग मैच भारत में कराएगा। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसी तरह भविष्य में भारत में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच प्रदर्शनी टेस्ट कराने की संभावना भी देखी जा रही है।

ऑस्ट्रेलिया में खेली गई पिछली एशेज सीरीज में कंगारू टीम ने इंग्लैंड को 4-1 से हराकर सीरीज अपने नाम की थी।

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) की हालिया वित्तीय रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के खिलाफ सीरीज बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सीरीज में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ECB की आय काफी हद तक भारत जैसी बड़ी ब्रॉडकास्ट सीरीज पर निर्भर करती है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2027 में पुरुष और महिला एशेज की मेजबानी के बावजूद बोर्ड को घाटे की आशंका है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अगली एशेज सीरीज 2027 में इंग्लैंड में खेली जाएगी। इससे पहले मार्च 2027 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर दोनों टीमों के पहले टेस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर डे-नाइट (पिंक बॉल) टेस्ट खेला जाएगा। यह मुकाबला एशेज सीरीज का हिस्सा नहीं होगा।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए।

भारत में नए क्रिकेट कंटेंट की संभावना

बीबीसी के 'स्टंप्ड' पॉडकास्ट में ग्रीनबर्ग ने कहा, 'हमें सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ECB और BCCI दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। भारत में क्रिकेट का नया कंटेंट ले जाने के मौके हैं। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है।'

उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट क्रिकेट मजबूत स्थिति में है और इसे आगे बढ़ाना जरूरी है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का व्यस्त कैलेंडर सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रीनबर्ग ने कहा, 'साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं। जितना क्रिकेट और कंटेंट हम देना चाहते हैं, उसके लिए शायद एक-दो महीने और चाहिए।'

मनोरंजन

कमल हासन बोले- सिस्टम सड़ चुका है, इमरान और वरुण समेत कई एक्टर्स समर्थन में उतरे

छात्रों की बात सुनना अहसान नहीं, हमारा फर्ज : करीना

नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधार आंदोलन को अब बॉलीवुड हस्तियों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। सलमान खान, आलिया भट्ट और अनन्या पांडे के बाद अब करीना कपूर खान, कमल हासन, वरुण धवन, इमरान खान और पीयूष मिश्रा भी छात्रों के पक्ष में आ गए हैं। करीना कपूर ने कहा कि देश के युवाओं की मांग सुनना कोई अहसान नहीं, बल्कि हमारा फर्ज है। वहीं कमल हासन ने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को सड़ा हुआ बताया है। इमरान खान ने मुंबई में खुद सड़क पर उतरकर छात्रों के साथ प्रदर्शन किया। एक्टर इमरान खान बुधवार को नीट धांधली के खिलाफ मुंबई में आयोजित एक विरोध मार्च में खुद शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में 'चलो संसद' मार्च के दौरान छात्रों पर हुए आंसू गैस और लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने लिखा था, जब मैंने देखा कि पुलिस छात्रों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज कर रही है, तो मेरा दिल टूट गया। जिन छात्रों ने मेहनत की, उन्हें सिस्टम ने धोखा दिया और जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाही तो उन्हें लाठियों से चुप करा दिया गया।

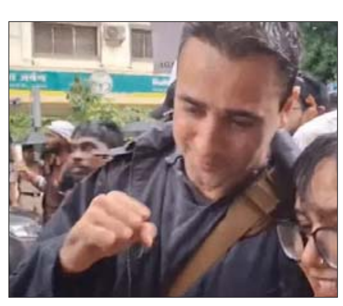

इमरान खान मुंबई प्रोटेस्ट में शामिल हुए।

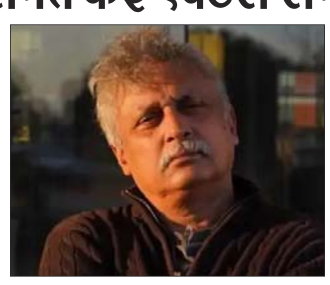

करीना बोलीं- बच्चे कल की तैयारी नहीं कर रहे, वे ही कल हैं

करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मैं पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे पर शांत थी, लेकिन अब चुप नहीं रह सकती। अपनी आवाज उठाने वाले युवाओं की अनदेखी करना नामुमकिन है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। शिक्षा से बच्चे को भरोसा और उम्मीद मिलती है। लेकिन शिक्षा तभी काम करती है जब बच्चों को इस पर विश्वास हो। अगर उन्हें लगेगा कि ईमानदारी, मेहनत और मेरिट का कोई मतलब नहीं है, तो उनका भरोसा उठ जाएगा।

कमल हासन बोले- सिस्टम सड़ चुका

एक्टर और नेता कमल हासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश के शिक्षा तंत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, जब एक बच्चा रोया था, तब हमें सुन लेना चाहिए था। हमने तब तक इंतजार किया जब तक कई बच्चों की मौत नहीं हो गई। एक ऐसा सिस्टम जहां सीखने की जगह कोचिंग ने ले ली है, उत्सुकता की जगह चिंता ने ले ली है और मेरिट की जगह अपराध ने ले ली है, वह सिस्टम पूरी तरह सड़ चुका है।

खेसारी लाल यादव पर बुरी तरह भड़कीं मलाइका अरोड़ा

वजह जानकर आपको भी आ सकता है गुस्सा

नई दिल्ली, एजेंसी

बॉलीवुड की क्वीन मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के एक वीडियो पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस क्लिप पर जब मलाइका की नजर पड़ी तो वह अपनी नाराजगी जताने से पीछे नहीं रहीं। यह वीडियो एक इवेंट का है, जहां खेसारी लाल यादव आए थे। जब वह पैपराजी को पोज देने के लिए आए तो वहां एक डॉग लेटा हुआ था। जिसे उन्होंने हटवाया। जब वह डॉग नहीं हट रहा था, तब कभी शख्स ने पैर से उसे खिसकाया तो कभी उसे हाथ से घसीट कर खेसारी के पास से ले गए। यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। इस बीच मलाइका अरोड़ा भी अपना गुस्सा जताने में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने गुरुवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर खेसारी का वही वीडियो रीशेयर किया और अपनी भड़ास निकाली। मलाइका अरोड़ा का खेसारी को लेकर किया गया ये पोस्ट अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि एक्ट्रेस हमेशा से ही डॉग लवर्स रही हैं ।

'सैयारा' के बाद ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे अहान पांडे

नई फिल्म की रिलीज डेट का एलान, 2027 में दस्तक देगी मूवी

नई दिल्ली। फिल्म 'सैयारा' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अहान पांडे (Ahaan Panday) की अगली फिल्म का इंतजार दर्शकों को बड़ी बेसब्री से है। अहान की अगली फिल्म का एलान काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है कि आखिर अली अब्बास जफर की ये अनटाइटल्ड मूवी पर्दे पर कब दस्तक देगी।

अहान पांडे के साथ इस फिल्म में शरवरी नजर आएंगीं। फिल्म का इंतजार दर्शकों को काफी वक्त से है। इस एक्शन फिल्म को अली अब्बास जफर बना रहे हैं और अब YRF ने फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया है। आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने अली अब्बास जफर की इस अनटाइटल्ड फिल्म के लिए 26 मार्च, 2027 की रिलीज डेट तय की है।

मतलब यह है कि फिल्म 2027 में गुड फ्राइडे के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि फिल्म में अहान-शरवरी (Sharvari) ही नहीं होंगे, बल्कि फिल्म में आपको अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) भी नजर आएंगे और फिल्म में बॉबी की दमदार एंट्री से धमाका जरूर होगा। वहीं फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे भी होंगे।

हालांकि इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता है कि फिल्म में आखिर एक्शन का लेवल कितना ज्यादा होगा। दरअसल फिल्म में एक्शन बड़े लेवल पर नजर आएगा। अब फिल्म को डायरेक्ट करने की कमान अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) ने संभाली है तो जाहिर फिल्म में एक्शन धमाकेदार ही होगा। अली अब्बास जफर इससे पहले गुंडे और टाइगर जैसी शानदार फिल्में बना चुके हैं। ऐसे में इस रोमांटिक एक्शन ड्रामा में मसाला भरपूर होगा।

8 साल बाद जॉनी डेप का धांसू कमबैक

हॉरर थ्रिलर एबेन्सर के ट्रेलर में 'खड़ूस बूढ़ा' बनकर कर दिया हैरान

नई दिल्ली। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जॉनी डेप (Johnny Depp) को 8 साल से बड़े पर्दे पर देखने का फैंस इंतजार कर रहे थे। अब आखिरकार अभिनेता कमबैक के लिए तैयार हैं। वह एक अलग अंदाज में वापसी कर रहे हैं और उनकी आगामी फिल्म का ट्रेलर देख लोगों के होश उड़ गए।

जॉनी डेप की कमबैक फिल्म एबेनेजरः एक क्रिसमस कैरोल (Ebenezer: A Christmas Carol) है। यह एक क्रिसमस फैंटेसी हॉरर थ्रिलर है जिसका निर्देशन टी. वेस्ट ने किया है। फिल्म में जॉनी डेप के अलावा अहम भूमिकाओं में एंड्रिया राइजबोरो, सैम क्लैफ्लिन, डेजी रिडले, आर्थर कोंटी, एली बैम्बर, चार्ली मर्फी और इयान मैककेलन जैसे कलाकार हैं।

फिल्म चार्ल्स डिकेंस की 'अ क्रिसमस कैरोल' (A Christmas Carol) पर बेस्ड है जिसमें एक कठोर और कंजूस बूढ़े आदमी एबेनेजर स्क्रूज की कहानी बताई गई है। एबेनेजर को क्रिसमस के त्योहार से नफरत है। क्रिसमस Eve से ठीक एक दिन पहले उसके मरे हुए बिजनेस पार्टनर जैकब मार्ले का भूत और तीन आत्माएं आती हैं और उसे उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाती हैं।

भूत और आत्माएं मिलकर उसे किस तरह बदल देती हैं, कहानी इसी के इर्द-गिर्द है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एबेनेजर (जॉनी डेप) आत्माओं से परेशान हो गया है।

जॉनी डेप की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म सिनेमाघरों में 13 नवंबर को रिलीज होने वाली है। साल 2018 के बाद से यह जॉनी का का पहला बड़ा हॉलीवुड प्रोजेक्ट है। फैंस उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं।

रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर

जॉनी डेप की फिल्म एबेनेजरः एक क्रिसमस कैरोल हॉरर के साथ-साथ कॉमेडी से भी भरी है, जिसकी एक झलक फिल्म के ट्रेलर में साफ दिखाई दे रही है। 24 जुलाई को रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर कॉमेडी, ड्रामा और हॉरर से भरी हुई है जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। फिल्म का सबसे बड़ा हाइलाइट 63 साल के जॉनी का लुक है। आप उन्हें एक पल के लिए पहचान नहीं पाएंगे।

जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई, पहले के 15% टैरिफ का आज आखिरी दिन

अमेरिका ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया

फैसला

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिका ने शुक्रवार से भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% टैरिफ लागू कर दिया है। यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट-1974 की धारा 301 के तहत फोर्स्ड लेबर (जबरन मजदूरी) से बने सामान को लेकर की गई है।

यह फैसला ऐसे दिन लागू हुआ, जब ट्रम्प प्रशासन का 15% अस्थायी ग्लोबल टैरिफ खत्म हो रहा है। यानी पुराना टैरिफ हटते ही उसकी जगह नया स्थायी टैरिफ लागू कर दिया गया।

अमेरिका ने 60 देशों पर 10% से 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इनमें 17 देशों पर 10% और 43 देशों पर 12.5% टैरिफ लगाया गया है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका को 10% वाले समूह में रखा गया है। अमेरिका के मुताबिक, इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाई है या उस दिशा में कदम उठाए हैं। शुरुआत में भारत पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। हालांकि बाद में भारत सरकार की ओर से श्रम मानकों और सप्लाई चेन की निगरानी से जुड़े कुछ नीतिगत सुधारों तथा अमेरिका के साथ लगातार बातचीत के बाद इसे घटाकर 10% कर दिया गया।

फेडरल नोट में कहा गया है कि जून में प्रस्तावित टैरिफ घोषित होने के बाद भारत ने 14 जून को अपनी विदेशी व्यापार नीति में संशोधन किया। अमेरिका का मानना था कि भारत ने श्रमिक अधिकारों की निगरानी, नियमों के पालन और सप्लाई चेन में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसी आधार पर प्रस्तावित टैरिफ में 2.5% की राहत दी गई।

10% टैरिफ लागू रहने का मतलब है कि भारत को पूरी छूट नहीं मिली है। यानी अमेरिका अब भी चाहता है कि भारत श्रम मानकों और फोर्स्ड लेबर से जुड़े नियमों को और प्रभावी ढंग से लागू करे। हालांकि 12.5% के बजाय 10% टैरिफ से भारतीय निर्यातकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त लागत का बोझ कुछ कम होगा। फोर्स्ड लेबर का मतलब ऐसी मजदूरी से है, जिसमें किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ काम कराया जाए।

भारत के किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ऐसे में अतिरिक्त 10% टैरिफ से उन सेक्टरों पर ज्यादा असर पड़ सकता है, जिनकी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता अधिक है। इनमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर उत्पाद, कृषि एवं फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग आइटम शामिल हैं।

अतिरिक्त टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे खरीदार दूसरे देशों के विकल्प तलाश सकते हैं या भारतीय निर्यातकों पर कीमत घटाने का दबाव बढ़ सकता है।

> **अमेरिका का कहना है कि अगर किसी देश से आयात होने वाला सामान फोर्स्ड लेबर से जुड़ा पाया जाता है, तो उस पर अतिरिक्त टैरिफ या आयात प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य कंपनियों पर दबाव बनाना है कि उनकी सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल न हो।**

बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन देंगे इस्तीफा

शेख हसीना के साथ संबंधों के लगे हैं आरोप

ढाका, एजेंसी

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही शुक्रवार को इस्तीफा दे देंगे। वह सत्ता से बेदखल की गईं प्रधानमंत्री शेख हसीना के पूर्व सहयोगी रहे हैं। यह घटनाक्रम हसीना के उस बयान के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद स्वदेश लौट रही हैं। शहाबुद्दीन के प्रवक्ता ने उनके इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई है। हालांकि, मामले की जानकारी रखने वाले तीन अधिकारियों ने बताया कि शेख हसीना के साथ पुराने संबंधों को देखते हुए सरकार ने उन पर पद छोड़ने के लिए दबाव डाला है। शहाबुद्दीन के त्यागपत्र के बाद शीर्ष पदों पर हसीना का कोई सहयोगी नहीं बचेगा। उनकी बांग्लादेश

वापसी की योजना में अभी पांच महीने बाकी हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनकी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को या तो जेल में डाल दिया गया है या वे भूमिगत हो गए हैं। शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश सरकार के लिए एक चुनौती होगी, जो देश में स्थिरता बहाल करने का प्रयास कर रही है।

प्रेट्र के अनुसार, अखबार प्रथम आलो ने सरकार के एक उच्च-स्तरीय सूत्र के हवाले से कहा है कि सरकार उन खबरों से नाराज है जिनमें कहा गया है कि शहाबुद्दीन ने हाल ही में हसीना से फिर से संपर्क साधने की कोशिश की थी।

फास्ट न्यूज़

चांदी आज 2,924 सस्ती, 2.19 लाख पर आई

नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमतों में आज यानी 24 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, एक किलो चांदी 2,924 रुपए घटकर 2.19 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,848 रुपए गिरकर 1.42 लाख रुपए पर आ गया है। एक दिन पहले चांदी 2.22 लाख रुपए और सोना 1.44 लाख रुपए पर था।

सेंसेक्स 331 अंक गिरकर 76,059 पर बंद

मुंबई। शेयर बाजार में आज यानी 24 जुलाई को गिरावट रही। सेंसेक्स 331 अंक की गिरावट के साथ 76,059 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 102 अंक की गिरावट है, ये 23,767 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, मेटल और रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। ब्रेंट क्रूड आज 96 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा, तो तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इसका असर भारत में पेट्रोल-डीजल पर दिख सकता है।

आशीष कुमार दश होंगे इंफोसिस के नए सीईओ

नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनी इंफोसिस ने आशीष कुमार दश को अपना नया CEO नियुक्त किया है। 23 जुलाई 2026 को पहली तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने इस लीडरशिप बदलाव का ऐलान किया। वे मौजूदा CEO और MD सलिल पारिख की जगह लेंगे।

यरुशलम में भारतीय मजदूर की हत्या फ्लैट में खून से लथपथ मिली लाश

यरुशलम, एजेंसी

इजरायल में काम करने वाले एक भारतीय व्यक्ति का शव यरूशलेम के कटामोन इलाके एक अपार्टमेंट में मिला है। स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि 40 वर्षीय व्यक्ति का शव घर के फर्श पर पड़ा मिला और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था।

मोरियाह पुलिस स्टेशन के प्रमुख युवल रूवेन ने बताया कि पुलिस को पीड़ित का शव घर में पड़ा हुआ, जिसके चारों ओर काफी खून फैला था। पुलिस ने कहा कि मौत की असली वजह अभी साफ नहीं है। इजरायली अधिकारियों ने अभी तक पीड़ित की पहचान जाहिर नहीं की है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच से आपराधिक पहलू का संकेत मिलता है। पुलिस ने दक्षिणी शहर इलात के एक 31 वर्षीय व्यक्ति को हत्या में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया है। संदिग्ध को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर

2024 तक इजरायल में लगभग 32,000 भारतीय कामगार थे। मंत्रालय ने बताया कि इनमें से लगभग 12,000 भारतीय अक्टूबर 2023 के बाद पहुंचे। नवंबर 2023 में हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत 6,365 भारतीय 2024 में इजरायल पहुंचे, जबकि बाकी लोग निजी माध्यमों से गए।

फरवरी में भारत और इजरायल इस बात पर सहमत हुए थे कि अगले पांच वर्षों में 50,000 और भारतीय कामगार इज़राइल आ सकते हैं। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक में लिया गया था। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इजराइल में भारतीय कामगारों के योगदान को सराहा था।

भारत और चीन के राजदूतों से मुलाकात करेंगे ■ 3 महीने में ही फैसले से पलटे

नेपाली पीएम बालेन शाह ने अपना ही नियम क्यों तोड़ा

काठमांडू, एजेंसी

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन शाह) पहली बार अपने बनाए नियम से हटकर विदेशी राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तय किया था कि वह किसी भी विदेशी राजदूत से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे।

नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बालेन शाह भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओमिंग से अलग-अलग मुलाकात करेंगे।

इसे नेपाल की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह अपने दोनों सबसे बड़े पड़ोसियों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखना

■ बालेन शाह ने 27 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।

चाहता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हितों का टकराव पैदा होता था और नेपाल के राष्ट्रीय हित प्रभावित होते थे। बालेन शाह ने तय किया कि वह किसी भी विदेशी राजदूत या प्रतिनिधि से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक अलग 'रैंक प्रोटोकॉल' बनाया था। नए नियम के मुताबिक, वह सिर्फ किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष/प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री स्तर के अधिकारी से ही अकेले व्यक्तिगत बैठक करेंगे। निचले स्तर के अधिकारियों, राजदूतों या उप-मंत्रियों से वे अकेले मिलने के बजाय विदेश मंत्रालय के माध्यम से या फिर ग्रुप मीटिंग के जरिए ही मिलेंगे।

बालेन शाह के पीएम बनने से पहले का नियम क्या था?

नेपाल में नई सरकार बनने पर खासकर भारत, चीन और अमेरिका जैसे प्रभावशाली देशों के राजदूत सीधे प्रधानमंत्री के निजी आवास पर जाकर अलग-अलग मुलाकात करते थे। इन बैठकों में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद नहीं होते थे और न ही इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता था।

■ बालेन शाह ने पीएम बनने के बाद विदेशी राजनयिकों से सिर्फ समूह (ग्रुप) में मुलाकात करने की नीति अपनाई।

एक ही दिन दोनों देशों के राजदूतों के साथ मीटिंग

बालेन शाह नहीं चाहते थे कि भारत या चीन में से किसी को यह लगे कि दूसरे देश को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने दोनों देशों के राजदूतों से एक ही दिन अलग-अलग मुलाकात करने का फैसला किया है। दोनों बैठकें एक के बाद एक होंगी, ताकि दोनों देशों के साथ समान व्यवहार का मैसेज जाए। नेपाल सरकार ने पुष्टि की है कि भारत और चीन के राजदूतों के साथ अलग-अलग बैठकें इसी सप्ताह होंगी। हालांकि, दोनों बैठकों की सटीक तारीख अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। नेपाल का विदेश मंत्रालय इन बैठकों की अंतिम तैयारियों में जुटा है।

नई शर्त जोड़ी, बोले- इजराइल से रिश्ते सुधारे सऊदी, न्यूक्लियर डील अटकी

सऊदी से परमाणु समझौता करके 24 घंटे में पलटे ट्रम्प

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिका और सऊदी अरब के बीच करीब दो दशक से अटके परमाणु समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर हुए, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही यह डील अटक गई है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने समझौते में नई शर्त जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि डील तभी आगे बढ़ेगी, जब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल से राजनयिक रिश्ते सामान्य करेगा।

ट्रम्प ने यह भी कहा कि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) की अनुमति नहीं मिलेगी।

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प की घोषणा से सऊदी अरब भी

हैरान रह गया। समझौते के मसौदे में कुछ शर्तें पूरी होने पर सऊदी अरब को अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलने की बात थी, लेकिन ट्रम्प ने इसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया।

दोनों देशों ने करीब दो दशक पहले परमाणु ऊर्जा सहयोग की पहल की थी। पिछले साल अक्टूबर में प्रारंभिक सहमति बनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध और कांग्रेस की संभावित आपत्तियों के कारण समझौता महीनों तक अटका रहा। पिछले सप्ताह ऊर्जा विभाग को लगा कि ट्रम्प की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इसकी घोषणा कर दी गई।

बिना बताए डील की घोषणा से ट्रम्प नाराज

वॉशिंगटन में हुए हस्ताक्षर समारोह में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प इस बात से नाराज थे कि राइट ने उनकी मंजूरी के बिना समझौते की घोषणा कर दी। इसके बाद फॉक्स न्यूज और वॉल स्ट्रीट जर्नल में हुई आलोचना से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस ने ऊर्जा विभाग से समझौते की घोषणा टालने को कहा था, लेकिन विभाग ने हस्ताक्षर समारोह भी किया और मीडिया में इसकी जानकारी भी दी। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की शर्त शुरू से ही ट्रम्प की नीति का हिस्सा थी। वहीं ऊर्जा विभाग ने किसी भी मतभेद से इनकार किया।

क्वांटस के प्रोजेक्ट सनराइज की पहली टेस्ट फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंची

फ्रांस से 19 घंटे की उड़ान भरकर इतिहास बनाया

नई दिल्ली, एजेंसी

ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन क्वांटस के विमान ने सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार 24 जुलाई की सुबह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लैंडिंग की।

विमान ने फ्रांस के टूलूज शहर से स्थानीय समयानुसार गुरुवार सुबह 7:33 बजे उड़ान भरी थी। 19 घंटे और 13 मिनट का लंबा सफर तय करके इसने मेलबर्न में टचडाउन किया। इस ऐतिहासिक टेस्ट फ्लाइट के दौरान एयरबस के 4 पायलट और 5 फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर विमान में मौजूद थे। टेस्ट फ्लाइट का मुख्य मकसद जेट के स्पेशल फ्यूल सिस्टम को जांचना था।

इस विमान में 20 हजार लीटर का एक अतिरिक्त रियर सेंटर फ्यूल टैंक है, जो आम A350-1000 एयरक्राफ्ट्स में नहीं होता है। यह फ्यूल टैंक विमान को 22 घंटे तक

लगातार उड़ने की क्षमता देता है।

क्वांटस के मुताबिक, यह विमान मेलबर्न से वापस टूलूज स्थित एयरबस मुख्यालय लौटेगा। इस वापसी यात्रा में क्वांटस के 2 पायलट और एयरबस का टेस्ट क्रू सवार रहेगा। क्वांटस ने साल 2017 में पहली बार 'प्रोजेक्ट सनराइज' का ऐलान किया था और 2022 में एयरबस को 12 कस्टमाइज्ड A350-1000ULR एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। पहले विमान की डिलीवरी इसी साल होनी थी, लेकिन अब इसमें देरी हुई है और पहला विमान अप्रैल 2027 में मिलेगा। इसके बाद बाकी 11 विमान अगले ढाई सालों में डिलीवर किए जाएंगे।

आरोप : बिना अनुमति एआई ट्रेनिंग में किताबों का किया था इस्तेमाल

एंथ्रोपिक हैरी पॉटर के पब्लिशर को देगी 19 मिलियन डॉलर का मुआवाजा

वाशिंगटन, एजेंसी

AI कंपनी ने अपने चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए बिना इजाजत हैरी पॉटर और कई अन्य किताबों का डेटा इस्तेमाल कर लिया था। अब 'हैरी पॉटर' किताबें छापने वाली कंपनी 'ब्लूम्सबरी' को AI बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक से करीब 19 मिलियन डॉलर मिलने की संभावना है। दरअसल, एंथ्रोपिक पर आरोप था कि उसने अपने 'क्लाउड' (Claude) AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बिना अनुमति और खरीदारी के हजारों कॉपीराइट वाली किताबों का इस्तेमाल किया।

यह मुकदमा उन लेखकों द्वारा दायर किया गया था जिन्होंने आरोप

लगाया था कि एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड एआई चैटबॉट को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी पुस्तकों का बिना अनुमति के उपयोग किया था। अमेरिकी इतिहास में कॉपीराइट का यह अब तक का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। हालांकि, इस समझौते के तहत एंथ्रोपिक को अपनी गलती स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह उन एआई कंपनियों के लिए अब तक के सबसे स्पष्ट वित्तीय परिणामों में से एक है जिन पर बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने का आरोप है।

> **मुकदमा दायर होने के बाद एक अमेरिकी कोर्ट ने समझौते के दायरे में आने वाली अपनी 14,087 पुस्तकों की पहचान की, जिसमें प्रति पुस्तक लगभग 3,000 डॉलर के मुआवजे का प्रस्ताव है, मुआवजे की इस राशि को संबंधित लेखकों और प्रकाशकों के बीच बांटा जाएगा।**

नकल करके बनाए गए एआई मॉडल

प्रकाशकों, लेखकों, समाचार संगठनों और कलाकारों की बढ़ती संख्या ने एआई कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। उनका आरोप है कि उनकी रचनाओं की नकल करके बिना सहमति या मुआवजे के शक्तिशाली एआई मॉडल बनाए गए हैं।

दूसरों की किस्मत बताने वाली खुद नहीं जान पाई अपना भविष्य!

मॉस्को में पावर बैंक फटने से झुलसीं इन्फ्लुएंसर अन्ना

मॉस्को, एजेंसी

रूस की महिला इन्फ्लुएंसर और ज्योतिष अन्ना ओटाविना के मॉस्को स्थित पेंटहाउस में रात के समय बिस्तर पर रखा पावर बैंक फट गया। पावर बैंक ओवरहीट होकर ब्लास्ट हुआ, इससे अन्ना ओटाविना की पीठ का 30 फीसदी हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया और बाल भी जल गए।

इस घटना के बाद अन्ना ने अपने फॉलोअर्स को सतर्क करते हुए चेतावनी दी है कि सोते समय या बिस्तर जैसी नरम सतहों पर पावर बैंक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्जिंग पर छोड़ना जानलेवा साबित हो सकता है।

वहीं इस घटना के बात इस बात की भी चर्चा हो रही है कि दूसरों की किस्मत बताने वाली ज्योतिष खुद

का भविष्य नहीं जान पाईं, जिसके कारण इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ा।

अन्ना ओटाविना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में बताया कि उनका पोर्टेबल चार्जर, जिसे उन्होंने फोन चार्ज करने के लिए बिस्तर पर रखा था, अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो गया। जिसके कारण ब्लास्ट हो गया और वो घायल हो गईं।

ओटाविना का कहना है पावर बैंक इसलिए ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वह इसे किसी ठोस, हवादार सतह के बजाय नरम बिस्तर पर रख दी थी, जिसके कारण वह बहुत गर्म हो गया।

वह पावर बैंक की ओर पीठ करके सो रही थी, जिसके कारण पीठ का लगभग 30 फीसदी हिस्सा जल गया और बाल भी झुलस गए।

जैसे ही वह उछली, आग की लपटें उनके बालों तक पहुंच चुकी थीं। जलते हुए बाल उसकी पीठ पर गिरे और उसकी त्वचा को झुलसा दिया, इससे पहले कि उन्हें समझ आता कि क्या हो रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि स्थिति एक छोटी सी चिंगारी से कहीं अधिक गंभीर थी। उनके तकिया और कंबल जल रहे थे, और पावर बैंक जमीन पर गिर गया था।

तमसा संकेत
tamsa.news@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्यादेवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ- 226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित कराकर तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) (पिन कोड- 224122) से प्रकाशित

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. 64107/96